नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 198, नई दिल्ली, शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

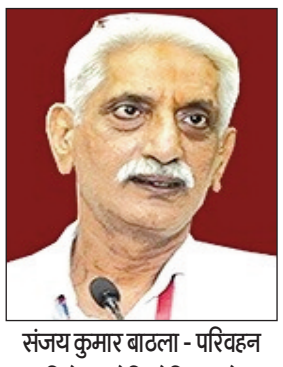
सफलता केवल मंज़िल तक पहुँचने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में छिपी होती है।

03 कार्तिक मास में दीपदान क्यों करना चाहिए?
06 कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में गणित : एक ऐसा कौशल जिसे खोना हमारे लिए
08 झारखंड के युवा क्रिकेटर शिखर का चयन भारतीय टीम में न्यूजीलैंड दौरे के लिए

परिवहन विशेष - विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट - जिम्मेदार कौन और सजा किसको?

दिल्ली में प्रदूषण मुक्त तभी संभव जब सजा जनता से पहले दी जाए सरकारी विभागों के आला अधिकारियों को

दिल्ली फिर प्रदूषित – कौन जिम्मेदार? हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, सजा सिर्फ जनता को?
मूल अधिकारों से वंचित दिल्लीवासी – जुर्माना – चालान – कार्रवाई भी उन्हीं पर
संवैधानिक अधिकारों का सच – सार्वजनिक परिवहन शून्य, गंदा पानी वो भी रात 3 बजे, जाम, टूटी सड़कें – गंदी गलियां



संजय कुमार बाठला - परिवहन विशेष इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो

मुख्य तथ्य - संवैधानिक अधिकार किताबों में नहीं
1. नलों के पानी,
2. सड़कों की हवा और
3. बसों की सीटों में दिखने चाहिए।

जब तक सार्वजनिक सुरक्षित सवारी शून्य है, गंदा पानी रात को आता है, तब तक जनता को दोषी ठहराना न्याय नहीं, अन्याय है।

प्रस्तावना: दिल्ली का AQI आज फिर 400+ Hazardous, यमुना में जहरीला झाग और नलों में रात 3 बजे आता है गंदा - बदबूदार पानी। सड़कें जाम से भरी, गड्ढों से टूटी, गलियां गंदे पानी से लबालब।

लेकिन जब कार्रवाई की बारी आती है तो PUC फेल पर चालान, GRAP में गाड़ी बैन, पानी बर्बाद करने पर जुर्माना - सिर्फ आम जनता पर।

क्या यही है संविधान का न्याय?

आज का सच - जमीनी हकीकत

1. सार्वजनिक सुरक्षित सवारी सेवा शून्य:
* डीटीसी की बस शून्य
* दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा कंपनी द्वारा चालित 50% बसें खटारा,
* Last Mile Connectivity नहीं,
* महिलाओं के लिए दिल्ली असुरक्षित,
* मेट्रो में ठसाठस भीड़।
* मजबूरन लोग निजी वाहन या ऑटो - असुरक्षित वाहनों पर चलने को मजबूर,
* और फिर उन्हीं पर चालान - जुर्माना और सजा।

2. पानी प्रदूषित – वो भी उपलब्ध रात 3 बजे: कई इलाकों (लक्ष्मी नगर, संगम विहार, उत्तम नगर) में सप्लाई रात 2-4 बजे आती है, वह भी पीली, बदबूदार। दिन भर इंतजार, मोटर का बिजली बिल अलग।

3. हवा प्रदूषित: अक्टूबर में ही AQI 350-450। स्रोत - वाहन धुआं 28%, धूल 22%, पराली 15%, उद्योग।

4. जाम से भरी सड़कें, टूटी सड़कें: PWD और MCD में उलझी सड़कें, हर 100 मीटर पर गड्ढा, सीवर ओवरफ्लो से गंदे पानी से भरी गलियां।

क्या कहते हैं हमारे संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार?

– अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने Subhash Kumar vs State of Bihar (1991) और MC Mehta vs Union of India में स्पष्ट कहा है - "स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है।" दिल्ली में यह अधिकार रोज उल्लंघन हो रहा है।

- अनुच्छेद 21A और 47 - सरकारी दायित्वः राज्य का कर्तव्य है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना और जन स्वास्थ्य में सुधार करना।

– अनुच्छेद 48A और 51A(g) – पर्यावरण संरक्षण: राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और नागरिकों का भी कर्तव्य है। पर क्या सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है?

– संविधान की प्रस्तावना – सामाजिक न्याय: जब सुविधा ही नहीं दी तो सजा कैसे?

नियम, कानून, अधिनियम और न्यायिक आदेश क्या कहते हैं?

1. जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981: DPCC को प्रदूषण रोकने की शक्ति, पर अमल शून्य। यमुना में 28 नालों का गंदा पानी आज भी सीधा गिर रहा है - NGT के 2015, 2021, 2024 के आदेशों के बाद भी।

2. मोटर वाहन अधिनियम 1988 / 2019 संशोधन: PUC, इंश्योरेंस, फिटनेस अनिवार्य, लेकिन धारा 166 के तहत सरकार की भी जिम्मेदारी - अच्छी सड़क, साइनेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना।

3. सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश:
- GRAP (Graded Response Action Plan) - जब AQI 400+ तो निर्माण बंद, BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल बंद। पर सवाल - विकल्प क्या दिया?
- MC Mehta केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था - "पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किए बिना निजी वाहनों पर रोक लगाना लोगों को सजा देने जैसा है।"
- NGT ने 2023 में कहा - "दिल्ली में पानी सप्लाई रात में देना मानवाधिकार का उल्लंघन है।"

सरकारी दायित्व बनाम जनता पर कार्रवाई - दोहरा मापदंड

सरकार का दायित्व (कानून में) - जमीनी हकीकत - जनता पर सजा
* स्वच्छ हवा देना (Air Act) - AQI 400+ - PUC न हो तो 2000 चालान
* स्वच्छ पानी देना (Water Act) - गंदा पानी रात 3 बजे - मोटर से पानी खींचो तो जुर्माना
* सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन बसें कम, - टूटी, लेट - Odd-Even में निजी कार पर 4000 जुर्माना
* गड्ढा-मुक्त सड़क (PWD Act) - 40% सड़कें टूटी - गड्ढे से एक्सीडेंट हो तो जनता जिम्मेदार
* सीवर सफाई (MS Act 2013) - गलियों में ओवरफ्लो - घर का पानी गली में आया तो चालान

विस्तृत जनहित विश्लेषण - कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कोई एक नहीं, सिस्टम की विफलता है:

1. MCD / DJB / PWD / DPCC / Transport Dept में तालमेल नहीं। एक सड़क 5 विभागों में बंटी।

2. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश कमः दिल्ली को 11,000 बसों की जरूरत, हैं 7,000, उनमें भी 1,500 रोज खराब।

3. Enforcement सिर्फ आसान टारगेट परः कैमरे से चालान काटना आसान, यमुना में गिरते नाले को बंद करना मुश्किल।

4. न्यायिक आदेशों का पालन नहीं: NGT के यमुना को 2025 तक साफ करने के आदेश का क्या हुआ? आज 2026 में झाग और ज्यादा है।

निष्कर्ष और जनहित में मांग: परिवहन विशेष की यह रिपोर्ट यह नहीं कहती कि चालान गलत है - नियम जरूरी है - पर सवाल है - पहले सुविधा या पहले सजा?

जनहित में 5 मांगें:

1. Right to Clean Air & Water को लागू करो: हर घर में दिन में 2 बार साफ पानी, AQI 200 से नीचे रखना सरकार की जवाबदेही तय हो, अधिकारी पर जुर्माना लगे।

2. Public Transport को Fundamental Service घोषित करो: जैसे बिजली-पानी, वैसे ही हर 500 मीटर पर 24x7 बस/ई-रिक्शा।

3. Challan से पहले Notice और विकल्प: PUC फेल है तो पहले फ्री PUC चेक कैंप, बस उपलब्ध नहीं तो कार बैन नहीं।

4. दिल्ली के लिए एकीकृत सड़क प्राधिकरण: एक ही एजेंसी टूटी सड़क, गंदी गली, जाम के लिए जिम्मेदार।

5. रात 3 बजे पानी सप्लाई पर रोक: NGT के आदेश का पालन, मानव गरिमा का सम्मान।

अंतिम पंक्ति: संवैधानिक अधिकार किताबों में नहीं, नलों के पानी, सड़कों की हवा और बसों की सीटों में दिखने चाहिए। जब तक सार्वजनिक सुरक्षित सवारी शून्य है, गंदा पानी रात को आता है, तब तक सिर्फ जनता को दोषी ठहराना न्याय नहीं, अन्याय है।



परिवहन विशेष समाचार पत्र से जुड़े सभी पाठकों और सहयोगियों के लिए विशेष सूचना

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं की हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 1. प्रतिदिन की देश विदेश की जानकारी 2. आपके वह आपके बच्चों के कैरियर, 3. आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित ज्ञानवर्धक आवश्यक जानकारिया, 4. आपकी सेहत से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारियां 5. शारीरिक बीमारियों से बचने के तरीके 6. धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान विश्व के सभी क्षेत्रों के ज्ञानदाताओं के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हम अपने चैनल द्वारा प्रतिदिन एक घंटे के कार्यक्रम "जनता की पुकार" में आपकी आवाज को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सरकार और सरकारी विभागों के साथ माननीय न्यायालयों से उसके उचित हल और उसके प्रति पालिसी लागू करवाने में मध्यांतर का माध्यम बनेंगे। आप सभी से अनुरोध आप के अपने शुरू होने वाले चैनल के माध्यम से अपनी शिकायतें, परेशानियां और अनुभव अन्य सभी से साझा करने के लिए तैयार एवं तत्पर रहे। आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा



पिंकी कुंडू



"साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टलों की मानव संसाधन क्षमता को तत्काल सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। राज्यों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित एवं समर्पित कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, पीड़ितों को सहायता तथा मामलों की प्रभावी जांच एवं प्रसंस्करण सुनिश्चित की जा सके। भोपाल के नागरिकों को ₹35.3 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का नुकसान होना इस चुनौती की गंभीरता और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।"

वर्ष 2026 के दौरान भोपाल में साइबर अपराध के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष के पहले नौ महीनों में साइबर अपराधियों द्वारा नागरिकों को ₹35.3 करोड़ से अधिक की आर्थिक हानि पहुंचाई गई। पुलिस अभिलेखों के अनुसार 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच कुल 4,179 साइबर अपराध शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों की बढ़ती संख्या के बावजूद अपर्याप्त स्टाफ, शिकायतों का अत्यधिक दबाव तथा e-Zero FIR पंजीकरण में विलंब के कारण साइबर अपराध प्राधिकरणों को गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

यह मामला बढ़ती साइबर धोखाधड़ी शिकायतों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु देशभर में साइबर अपराध रिपोर्टिंग एवं प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता संबंधी व्यापक चिंता को उजागर करता है।

मामले का विवरण

वित्तीय प्रभाव

1. वर्ष 2026 के प्रथम नौ महीनों में भोपाल के नागरिकों को साइबर अपराधियों द्वारा ₹35.3 करोड़ से अधिक की आर्थिक हानि हुई।

2. इसी अवधि में कुल 4,179 साइबर अपराध शिकायतें दर्ज की गईं।

e-Zero FIR पंजीकरण की स्थिति

1. राज्य साइबर अपराध मुख्यालय द्वारा पंजीकरण के लिए 962 e-Zero FIR अग्रेषित की गईं।

2. इनमें से 943 मामलों को भोपाल के विभिन्न पुलिस थानों में नियमित FIR के रूप में पंजीकृत किया गया।

3. साइबर अपराध अधिकारियों ने स्वीकार किया कि प्राप्त शिकायतों की संख्या, पंजीकृत FIR की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है।

संशोधित पंजीकरण सीमा

1. साइबर वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में e-Zero FIR दर्ज करने की न्यूनतम सीमा ₹1 लाख से घटाकर ₹25,000 कर दी गई है।

2. इस छूट के बावजूद शिकायतों की संख्या साइबर अपराध तंत्र की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक बनी हुई है।

शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया

वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारियों के अनुसारः

1. पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करते हैं।

2. कॉल स्वतः डायल-112 पर स्थानांतरित हो जाती है।

3. डायल-112 एक टोकन नंबर जारी करता है और शिकायतकर्ता का मूल विवरण राज्य साइबर अपराध मुख्यालय को भेजता है।

4. इसके बाद विशेष साइबर अपराध टीमें पीड़ितों से संपर्क कर e-Zero FIR पंजीकरण हेतु आवश्यक विस्तृत जानकारी एकत्र करती हैं।

एक प्रमुख समस्या यह सामने आई है कि अनेक शिकायतकर्ता डायल-112 द्वारा जारी टोकन नंबर को ही FIR नंबर समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह केवल शिकायत प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है।

मानव संसाधन एवं परिचालन चुनौतियां

अत्यधिक शिकायत भार

1. राज्य साइबर अपराध मुख्यालय को प्रतिदिन लगभग 1,500 से 1,600 शिकायतें प्राप्त होती हैं।

2. एक शिकायत की जांच एवं आवश्यक जानकारी एकत्र करने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है।

वर्तमान कॉल-बैक टीमें

पीड़ितों से संपर्क करने और FIR पंजीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए पांच विशेष टीमें गठित की गई हैं:

- भोपाल में 2 टीमें
- इंदौर में 1 टीम
- ग्वालियर में 2 टीमें

पीड़ितों को प्रतिक्रिया में विलंब

1. वर्तमान में केवल लगभग 65% शिकायतकर्ताओं को उसी दिन वापस कॉल प्राप्त हो पाती है।

2. पूर्व में यह दर मात्र 29% थी। यद्यपि इसमें सुधार हुआ है, फिर भी शिकायत निस्तारण में उल्लेखनीय विलंब बना हुआ है।

स्टाफ की कमी

1. राज्य साइबर अपराध मुख्यालय में कुल 255 कर्मियों का स्वीकृत/उपलब्ध बल है।

2. अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि साइबर अपराध शिकायतों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने के लिए वर्तमान मानव संसाधन अपर्याप्त है।

विश्लेषण

भोपाल का अनुभव साइबर अपराध शिकायतों की बढ़ती संख्या और संस्थागत प्रतिक्रिया क्षमता के बीच मौजूद गंभीर अंतर को उजागर करता है।

प्रमुख चिंताएं

1. शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव।

2. कॉल-बैक प्रक्रिया में विलंब, जिससे धोखाधड़ी वाले लेन-देन को समय रहते रोकने की संभावना घट जाती है।

3. टोकन नंबर एवं FIR पंजीकरण की स्थिति को लेकर आम जनता में भ्रम।

4. शिकायतों की तुलना में FIR की कम संख्या, जिससे पीड़ितों में असंतोष और जांच में देरी होती है।

5. म्यूल खातों के माध्यम से धनराशि के त्वरित स्थानांतरण के कारण धन की रिकवरी की संभावनाओं में कमी।

वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ घंटों की देरी भी संदिग्ध लेन-देन को फ्रीज करने तथा धनराशि की रिकवरी की संभावना को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

अनुशंसाएं

तात्कालिक उपाय

1. राज्य साइबर अपराध मुख्यालय एवं साइबर शिकायत केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए।

2. शिकायतों के निस्तारण के लिए 24×7 समर्पित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं।

3. डायल-112, साइबर हेल्पलाइन 1930, बैंकों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

4. प्रारंभिक शिकायत सत्यापन प्रक्रिया को स्वचालित बनाकर मानव श्रम का बोझ कम किया जाए।

5. जनता को टोकन नंबर और e-Zero FIR के बीच अंतर के संबंध में जागरूक किया जाए।

दीर्घकालिक उपाय

1. जिला स्तर पर साइबर शिकायत प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएं।

2. AI-सक्षम शिकायत वर्गीकरण एवं प्राथमिकता निर्धारण प्रणाली विकसित की जाए।

3. प्रशिक्षित साइबर विश्लेषकों एवं डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति कर जांच इकाइयों को सुदृढ़ किया जाए।

4. शिकायत लंबितता एवं प्रतिक्रिया समय की निगरानी हेतु रियल-टाइम डैशबोर्ड विकसित किए जाएं।

5. शिकायतों की संख्या के आधार पर समय-समय पर मानव संसाधन मूल्यांकन किया जाए।

भोपाल के नागरिकों को नौ महीनों में ₹35.3 करोड़ से अधिक की आर्थिक हानि तथा 4,179 साइबर अपराध शिकायतों का प्राप्त होना देश में बढ़ते साइबर खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। यह मामला स्पष्ट करता है कि वर्तमान शिकायत प्रबंधन तंत्र अत्यधिक शिकायत भार और सीमित मानव संसाधनों के कारण दबाव में कार्य कर रहा है। नागरिकों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण तथा साइबर अपराधों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ क्षमता में वृद्धि, प्रक्रिया स्वचालन तथा सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

मिशन नशामुक्त भारत @ 31 दिसंबर 2029 नशा माफियाओं की उलटी गिनती शुरू!

नेटवर्क होगा ध्वस्त? NDPS 1985, PITNDPS 1988 और PMLA 2002 का निर्णायक प्रहार — हर थाने की जवाबदेही तय हुई तो टूटेगी ड्रग माफियाओं की कमर

लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं, गोंदिया महाराष्ट्र

तथ्य एक नजर में

- संकल्प मंच: 21 अक्टूबर 2026, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, पुलिस स्मृति दिवस — केंद्रीय गृहमंत्री की दोटूक ललकार

- महालक्ष्य: 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त भारत — शेष 2026, 2027, 2028, 2029 इस लड़ाई को समर्पित

- संदेश: मादक पदार्थ भावी पीढ़ियों के लिए खतरा, अर्थव्यवस्था पर बोझ, राष्ट्रविरोधी फंडिंग का माध्यम

- कानूनी हथियार: NDPS Act 1985 — कठोर सजा, वाणिज्यिक मात्रा पर 10-20 वर्ष तक कारावास, PITNDPS 1988 — निवारक निरोध, PMLA 2002 — अवैध कमाई पर वित्तीय प्रहार

- संस्थागत तंत्र: NCORD — एजेंसियों में समन्वय, NIDAAN पोर्टल — अपराधी डेटा साझा, MANAS हेल्पलाइन 1933 — नागरिक सूचना (शुरू 18 जुलाई 2024)

- पृष्ठभूमि: गृहमंत्री ने कहा — 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति का लक्ष्य, अब नशे पर निर्णायक वार

मुख्य बिंदु

- 1. पुलिस थाने से अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक: मिशन अब सिर्फ छापेमारी नहीं, पूरी सप्लाई चेन — आर्थिक लाभ और डिजिटल नेटवर्क को तोड़ने का

- 2. अपराध का नया चेहरा: पारंपरिक तस्करी से हटकर सोशल मीडिया, डार्कनेट, क्रिप्टो लेनदेन, सिंथेटिक ड्रग्स — साइबर जांच अनिवार्य

- 3. कानून सख्त, क्रियान्वयन कसौटी: दोषसिद्धि दर, विशेष अदालतों में तेज सुनवाई, गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य ही वास्तविक दबाव बनाएंगे

- 4. मांग और पुनर्वास: सिर्फ आपूर्ति रोकने से नहीं, लत से जूझ रहे युवाओं के उपचार, परामर्श, परिवार सहयोग और पुनर्वास से ही स्थायी मुक्ति

- 5. राजनीति से परे: पंजाब 2027 चुनाव चर्चा के बावजूद मूल्यांकन का पैमाना — नेटवर्क टूटे? युवाओं तक पहुंच घटी? सूचना देने वालों की सुरक्षा बढ़ी?

विस्तृत महा-विश्लेषण

1. पुलिस स्मृति दिवस से राष्ट्रीय संकल्प क्यों? स्मृति दिवस बलिदान को याद करने का दिन है। उसी मंच से नशे के विरुद्ध अभियान को प्राथमिकता बनाना पुलिस बलों के सामने नई जिम्मेदारी है। सफलता का पैमाना सिर्फ जब्ती के किलो नहीं, बल्कि अवैध आपूर्ति कितनी घटी, युवा कितने बचे, परिवारों को कितनी सहायता मिली — यह होना चाहिए।

2. पारंपरिक तस्करी से डिजिटल नेटवर्क तक चुनौती पहले गुप्त संपर्क, सीमावर्ती तस्करी, स्थानीय वितरक। आज — ऑनलाइन संपर्क, छद्म पहचान, इंटरनेट वित्तीय लेनदेन, अंतरराज्यीय नेटवर्क। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, डार्कनेट बाजार, क्रिप्टो लेनदेन। इसलिए प्रशिक्षित साइबर जांच दल, डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय जांच, अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी। लेकिन तकनीक का उपयोग कानून, निजता और न्यायसंगत जांच के दायरे में हो।

3. भारत के कानूनी हथियार NDPS 1985 में उत्पादन, कब्जा, बिक्री, परिवहन पर कठोर दंड। PITNDPS 1988 में निवारक निरोध की व्यवस्था। PMLA 2002 में ड्रग मनी को वैध बनाने की कोशिशों पर प्रहार। पुलिस, NCB, BSF, औषधि नियंत्रण और वित्तीय एजेंसियों का तालमेल, डिजिटल साक्ष्य, समयबद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया जरूरी। कठोरता नहीं, निष्पक्ष जांच और दोषसिद्धि ही अपराधियों पर दबाव बनाती है।

4. NCORD, NIDAAN, MANAS — समन्वय से जनभागीदारी NCORD समन्वय का केंद्र, NIDAAN अपराधी जानकारी साझा करने का प्लेटफॉर्म, MANAS 1933 पर नागरिक तस्करी, अवैध खेती की सूचना दे सकते हैं और पुनर्वास सहायता पा सकते हैं। उपयोगिता तभी जब शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, गोपनीयता सुरक्षा और जिलों में नियमित आकलन हो।

5. क्या 6 महीने में कारोबार समाप्त हो सकता है? केंद्रित अभियान से जिले में बड़ा परिणाम संभव है, पर पूरे देश में 6 महीने में शून्य तक पहुंचना ठोस प्रमाण बिना दावा होगा। कारण — मांग भी समस्या है। उपचार, परामर्श, पुनर्वास के बिना बाजार दोबारा उभरेगा। यदि हर थाने में शिकायत पर कार्रवाई, मेडिकल स्टोरों की नियमबद्ध जांच, युवाओं में जागरूकता और नशा प्रभावितों को सहायता मिले तो 2028 तक उल्लेखनीय प्रगति संभव है।

6. क्या यह राजनीतिक रणनीति है? पंजाब में नशा मुद्दा राजनीतिक रहा है। पर समय सीमा को सिर्फ चुनावी लाभ कहना उचित नहीं। मूल्यांकन परिणामों से हो — क्या बड़े नेटवर्क टूटे? युवाओं तक पहुंच घटी? दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई? नशा पीड़ितों को उपचार मिला?

निष्कर्ष: 31 दिसंबर 2029 सिर्फ समयसीमा नहीं, भावी पीढ़ी से वादा है। केंद्र, राज्य, पुलिस, एजेंसियां, न्यायपालिका, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल और नागरिक समाज साझा रणनीति से काम करें तो अवैध कारोबार गंभीर रूप से कम हो सकता है। इसके लिए थानों में जवाबदेही, भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच, डिजिटल पहचान, अवैध कमाई पर वार, तेज न्याय और पुनर्वास को समान महत्व देना होगा। नशे के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की सुरक्षा भी अभियान का हिस्सा होनी चाहिए।

संपादकीय टिप्पणी: नशामुक्त भारत केवल सरकार का नहीं, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है — कलियुग से सतयुग की ओर बढ़ने का अर्थ अन्याय और लोभ पर सदाचार की विजय है।



बुढ़ापा और रोग प्रतिरोधक क्षमता: टीकाकरण का महत्व

डॉ. विजय गर्ग



बुढ़ापा जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जीवन के इस पड़ाव में अच्छे स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक प्रणाली का धीरे-धीरे कमजोर होना भी शामिल है। इसके कारण बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कोविड-19 तथा शिंगल्स जैसी बीमारियों की गंभीर जटिलताएं होने की आशंका भी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में टीकाकरण स्वास्थ्य की रक्षा, बीमारियों की रोकथाम और स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

उम्र बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों घटती है?

रोग प्रतिरोधक प्रणाली शरीर को वायरस और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह प्रणाली संक्रमणों को पहचानने और उनसे लड़ने में पहले जितनी प्रभावी नहीं रह जाती। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में 'इम्यूनोसेनेसेंस' (Immunosenescence) कहा जाता है। इसके कारण शरीर की नए संक्रमणों और टीकों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम हो सकती है।

बुजुर्गों में मधुमेह, हृदय रोग, सांस संबंधी समस्याएं और गुर्दों की बीमारियां जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी अधिक पाई जाती हैं। ये बीमारियां संक्रमण होने पर गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ा सकती हैं। कुछ बुजुर्गों में पोषक तत्वों की कमी, शारीरिक गतिविधियों में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच भी उनकी संवेदनशीलता बढ़ा सकती है।

इसलिए जो संक्रमण किसी युवा व्यक्ति में हल्की बीमारी पैदा करता है, वही बुजुर्ग के लिए अस्पताल में भर्ती होने या लंबे समय तक स्वस्थ होने में कठिनाई का कारण बन सकता है। इसी वजह से वृद्धावस्था में बीमारियों की रोकथाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

टीकाकरण: सुरक्षा की ढाल

टीके शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को विशेष रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं या वायरस की पहचान करना और उनके संपर्क में आने पर अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया देना सिखाते हैं। हालांकि कोई भी टीका प्रत्येक संक्रमण को पूरी तरह नहीं रोक सकता, लेकिन कई टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों में यह गंभीर बीमारी, जटिलताओं और मृत्यु के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है।

बुजुर्गों के लिए टीकाकरण केवल बचपन की स्वास्थ्य आवश्यकता नहीं है। यह वयस्क जीवन के दौरान भी निवारक स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहता है।

*1. इन्फ्लुएंजा का टीका: * मौसमी फ्लू बुजुर्गों में गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है, विशेषकर उन लोगों में जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार हर वर्ष लगाया जाने वाला फ्लू का टीका गंभीर बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है।

*2. न्यूमोकोकल टीके: * न्यूमोकोकल बैक्टीरिया निमोनिया, रक्त संक्रमण और मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पात्र बुजुर्गों, विशेषकर कुछ दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय सलाह और संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार इन टीकों से लाभ मिल सकता है।

*3. कोविड-19 के टीके: * कोविड-19 बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। वर्तमान स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित टीकाकरण कराने से गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। टीके की आवश्यकता व्यक्ति की पिछली खुराकों, स्वास्थ्य स्थिति और वर्तमान दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है।

*4. शिंगल्स का टीका: * शिंगल्स एक ऐसी बीमारी है जो चिकनपॉक्स पैदा करने वाले वायरस के दोबारा सक्रिय होने से होती है। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ जाता है। इससे शरीर पर दर्दनाक छाले हो सकते हैं और कई बार छाले ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक दर्द बना रहता है। पात्र वयस्कों के लिए स्थानीय दिशानिर्देशों और टीके की उपलब्धता के अनुसार यह टीका उपयोगी हो सकता है।

*5. टेटनस और अन्य टीके: * बुजुर्गों को अपने टीकाकरण के पुराने रिकॉर्ड, स्वास्थ्य स्थिति, यात्रा की योजनाओं और अन्य जोखिमों के आधार पर टेटनस के बूस्टर या दूसरे टीकों की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हेपेटाइटिस-बी और अन्य टीके भी उपयुक्त हो सकते हैं।

प्रत्येक बुजुर्ग के लिए एक ही टीकाकरण कार्यक्रम उपयुक्त नहीं होता। टीकों का चयन उम्र, चिकित्सा इतिहास, पहले लगाए गए टीकों, उपलब्धता और संबंधित स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

बीमारी की रोकथाम से भी अधिक लाभ

टीकाकरण के लाभ केवल संक्रमण से बचाव तक सीमित नहीं हैं। गंभीर बीमारियों से बचाव बुजुर्गों की चलने-फिरने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद कर सकता है। इससे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता, परिवार पर आर्थिक बोझ और दैनिक जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं।

संक्रमण के कारण हृदय या फेफड़ों की पहले से मौजूद बीमारियां बिगड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक कमजोरी और दूसरों पर निर्भरता भी बढ़ सकती है। इसलिए गंभीर संक्रमणों के खतरे को कम करना स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

टीकाकरण से परिवार और समाज को भी लाभ होता है। टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त बुजुर्गों में गंभीर बीमारी की आशंका कम हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में संक्रमण के प्रसार का खतरा भी घट सकता है। हालांकि, संक्रमण और उसके प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा प्रत्येक टीके और बीमारी में अलग-अलग हो सकती है।

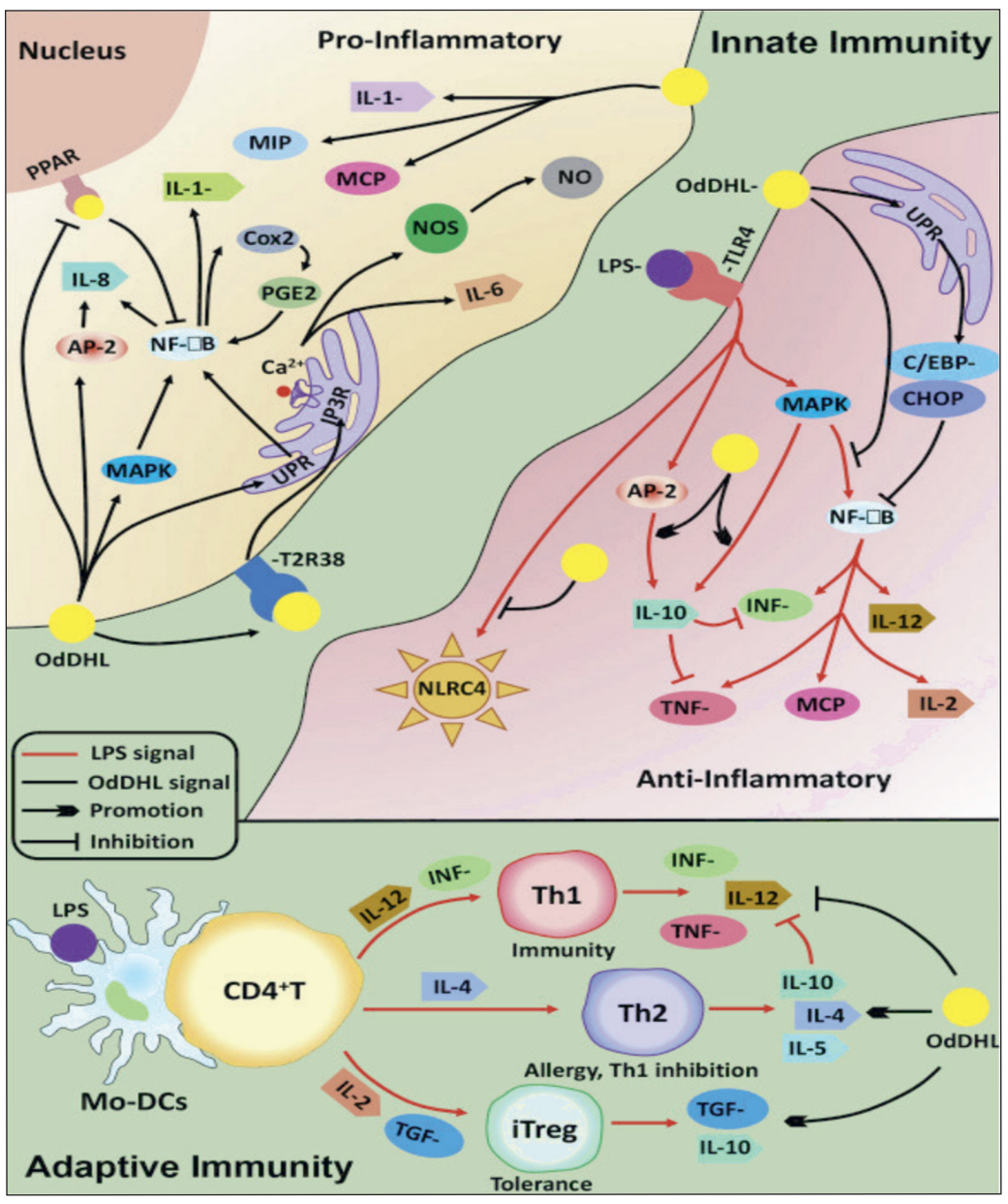
आम गलत धारणाओं को दूर करना

टीकाकरण के लाभों के बावजूद अनेक बुजुर्ग आवश्यक टीके नहीं लगवाते। कुछ लोग मानते हैं कि टीके केवल बच्चों के लिए जरूरी हैं, जबकि कुछ को इनके दुष्प्रभावों का डर होता है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि पौष्टिक भोजन ही शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है।

ऐसी धारणाएं बुजुर्गों को अनावश्यक जोखिम में डाल सकती हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये टीकाकरण का विकल्प नहीं बन सकते।

अधिकांश टीकों के दुष्प्रभाव हल्के और अस्थायी होते हैं, जैसे टीका लगाने वाली जगह पर दर्द, थकान या हल्का बुखार। गंभीर प्रतिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, हालांकि व्यक्तिगत जोखिम अलग-अलग हो सकते हैं। जिन लोगों को पहले किसी टीके या उसके घटकों से गंभीर एलर्जी हुई हो, उन्हें अगली खुराक लेने से पहले चिकित्सक को इसकी जानकारी अवश्य देनी चाहिए।

टीकाकरण से संबंधित निर्णय अफवाहों या सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रमाणित जानकारियों के बजाय विश्वसनीय चिकित्सकीय सलाह के आधार पर लेने चाहिए।



परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका

बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, टीकाकरण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए और योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आवश्यक टीकों के बारे में सलाह लेनी चाहिए।

डॉक्टरों को टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित करने से पहले बुजुर्ग व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास, वर्तमान बीमारियों, पहले लगाए गए टीकों और संभावित निषेधों की समीक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र स्पष्ट जानकारी, सुविधाजनक अपॉइंटमेंट और समय पर टीका लगवाने की याद दिलाने वाली व्यवस्था के माध्यम से इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं।

सरकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी जागरूकता अभियान मजबूत करने चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां निवारक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बुजुर्गों को टीकाकरण का महत्व समझाने और उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

बुजुर्गों को किसी बीमारी के फैलने या अपने क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। निवारक स्वास्थ्य देखभाल सबसे प्रभावी तब होती है, जब इसकी योजना पहले से बनाई जाए।

निष्कर्ष

उम्र बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बीमारी और आत्मनिर्भरता का समाप्त होना अनिवार्य है। टीकाकरण के साथ नियमित चिकित्सकीय देखभाल, संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ आदतें बुजुर्गों को कई गंभीर संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकती हैं।

प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को जीवन के इस पड़ाव में सम्मान, आत्मविश्वास और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। समय पर टीकाकरण इस लक्ष्य की दिशा में एक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण कदम है।

बुढ़ापे में रोग प्रतिरोधक क्षमता की रक्षा केवल संक्रमणों से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता बनाए रखने, परिवारों की सुरक्षा करने और जीवन में स्वस्थ वर्षों की संख्या बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक

हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक धरोहर - आस्था के पीछे छिपा है विज्ञान

हमारे ऋषि-मुनियों ने जो परंपराएं बनाईं, वो केवल धर्म नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान थीं। आज आधुनिक साइंस भी उन्हें सही मान रही है।



परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

आज की पीढ़ी अक्सर हमारी पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास समझ लेती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी हर परंपरा के पीछे स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और पर्यावरण से जुड़ा वैज्ञानिक कारण छिपा है।

1. शंख बजाना

शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। इसकी गूंज से वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और मन में सकारात्मक तरंगें फैलती हैं, जिससे एकाग्रता बढ़ती है।

2. हवन

हवन में आम की लकड़ी, घी और जड़ी-बूटियों के प्रयोग से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि हवन से हवा में मौजूद बैक्टीरिया 30 दिनों तक नियंत्रित रहते हैं। यह पर्यावरण शुद्धि का सबसे बड़ा वैदिक उपाय है।

3. मंदिर की घंटी

मंदिर में घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक गूंजती है। यह ध्वनि हमारे शरीर के सातों चक्रों को सक्रिय करती है। घंटी की आवाज से मन एकाग्र और शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

4. तिलक लगाना

माथे के बीच आज्ञा चक्र होता है। यहां चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने से मस्तिष्क शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मविश्वास व ऊर्जा का संचार होता है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है।

5. मौली (कलावा) बांधना

कलाई पर मौली बांधना सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं है। कलाई की नसों पर इसका दबाव पड़ने से रक्तचाप, हृदय और मधुमेह जैसी बीमारियों में लाभ मिलता है। यह त्रिदोष - वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने का प्रतीक है।

6. दीप प्रज्वलन

घी का दीपक जलाने से निकलने वाले प्रकाश से नकारात्मक आयन सक्रिय होते हैं जो मानसिक शांति और सकारात्मकता का संचार करते हैं। दीपक की लौ लगातार देखने से आंखों की ज्योति भी बेहतर होती है।

7. तुलसी पूजन

तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और अपने आसपास ओजोन लेयर बनाता है। इसके पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो घर के वातावरण को पवित्र और रोगमुक्त बनाते हैं।

8. पीपल पूजन

पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन (प्राणवायु) देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे जीवनदायी वृक्ष कहा गया है। पीपल के नीचे दीपक जलाने से पर्यावरण शुद्ध होता है।

निष्कर्ष: हमारी संस्कृति अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। जरूरत है कि हम अपनी नई पीढ़ी को इसका वैज्ञानिक महत्व समझाएं।

Vediccodes
VASTU • NUMEROLOGY • ASTROLOGY
आपके दिन की शुरुआत, पारुल भटनागर के साथ
विशेषज्ञ एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट
परिवहन विशेष News

धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

23 अक्टूबर 2026 | दिन का अंक: 7 — विश्लेषण, अंतर्ज्ञान, आत्मचिंतन, शोध और आंतरिक स्पष्टता

मूलांक 1

धन व करियर: दिन का अंक 7 आपकी नेतृत्व ऊर्जा को थोड़ा धीमा करके रणनीतिक सोच की ओर ले जाता है। सभी तथ्य स्पष्ट होने से पहले निर्णय आगे बढ़ाने के बजाय शोध, समीक्षा और शांत योजना अधिक लाभ दे सकती है।
रिश्ते: आप सीधा उत्तर चाह सकते हैं, जबकि सामने वाले को सोचने के लिए समय चाहिए हो सकता है। उनकी स्पेस का सम्मान करें और चुप्पी को अहंकार का विषय न बनाएं।
सावधानी: अधीरता, परिणाम के लिए दबाव और केवल स्वतंत्रता साबित करने के लिए आर्थिक निर्णय से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: कदम उठाने से पहले रुकें और एक अच्छी तरह जांचे निर्णय को दिन की दिशा बनाएं।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 7 आपकी सहज समझ को और गहरा करता है। साझेदारी, खरीद या आर्थिक प्रतिबद्धता से पहले विवरण ध्यान से देखें; तथ्य के साथ जुड़ा अंतर्ज्ञान उपयोगी रहेगा।
रिश्ते: भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी। आप अनकही बात भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हर चुप्पी में छिपा अर्थ खोजने से बचें।
सावधानी: अधिक सोचने, आत्म-संदेह और भावनात्मक दूरी से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें, शांत तरीके से उसकी पुष्टि करें और एक जरूरी भावना स्पष्ट कहें।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 7 आपकी रचनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण ऊर्जा में गहराई लाता है। तुरंत ध्यान पाने के बजाय लेखन, शोध, शिक्षण या किसी विचार को बेहतर करना अधिक उपयोगी रहेगा।
रिश्ते: आज सतही बातचीत से अधिक अर्थपूर्ण संवाद लाभ देगा। हर चुप्पी भरने के बजाय ध्यान से सुनें और सच्चाई से बोलें।
सावधानी: बिखरे फोकस, गॉसिप और केवल बोरियत दूर करने के लिए खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक रचनात्मक विचार को गहराई दें और उसे सोच-समझकर बनाई योजना में बदलें।

मूलांक 4

धन व करियर: दिन 7 आपकी विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक प्रकृति के अनुकूल है। खर्च, सिस्टम और छिपी कमजोरियों की समीक्षा करने के लिए अच्छा दिन है ताकि वे आगे महंगी समस्या न बनें।
रिश्ते: आप सामान्य से भी अधिक शांत रह सकते हैं। विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन चुप्पी को भावनात्मक ठंडापन न बनने दें।
सावधानी: पूर्णता की जिद, संदेह और हर विवरण स्पष्ट होने तक काम टालने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण विवरण जांचें और एक भावना स्पष्ट शब्दों में कहें।

मूलांक 5

धन व करियर: दिन 7 आपकी तेज ऊर्जा को धीमा करके गहराई से जांचने को कहता है। नया प्रस्ताव या संपर्क आकर्षक हो सकता है, लेकिन हां कहने से पहले शर्तें और लंबी अवधि का मूल्य देखें।
रिश्ते: आप उत्साह चाह सकते हैं, जबकि दूसरे शांति पसंद करें। अलग गति का सम्मान करें और दिन को रोमांचक बनाने के लिए अनावश्यक तनाव न बनाएं।
सावधानी: अचानक खरीदारी, जोखिमपूर्ण शॉर्टकट और बेचैनी में निर्णय से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: जिज्ञासा को भटकाव के बजाय शोध में लगाएं।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 7 आपको धन और काम के मामलों में बाहरी चमक से आगे देखने को कहता है। नई जिम्मेदारी लेने से पहले नियमित खर्च, वादे और मौजूदा दायित्वों की समीक्षा करें।
रिश्ते: आप निकटता चाह सकते हैं, लेकिन आज आत्मचिंतन की ऊर्जा भी मजबूत है। सामने वाले की स्पेस को प्यार की कमी न समझें।
सावधानी: जरूरत से ज्यादा देने, भावनात्मक अनुमान और आराम के लिए खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: शांत संतुलन बनाएं और एक आर्थिक या भावनात्मक प्रतिबद्धता की समीक्षा करें।

मूलांक 7

धन व करियर: आपके मूलांक 7 और दिन के अंक 7 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। विश्लेषण, अंतर्ज्ञान, शोध और आंतरिक स्पष्टता बढ़ेगी। रणनीति के लिए श्रेष्ठ दिन है; बड़े आर्थिक कदम में जल्दबाजी न करें।
रिश्ते: आप गहराई से महसूस कर सकते हैं, लेकिन कम व्यक्त करेंगे। सरल और ईमानदार संवाद अनावश्यक दूरी या गलतफहमी रोक सकता है।
सावधानी: अलगाव, निराशावाद, संदेह और लगातार विश्लेषण में फंसने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एकांत से स्पष्टता लें और एक सत्यापित समझ पर कदम उठाएं।

मूलांक 8

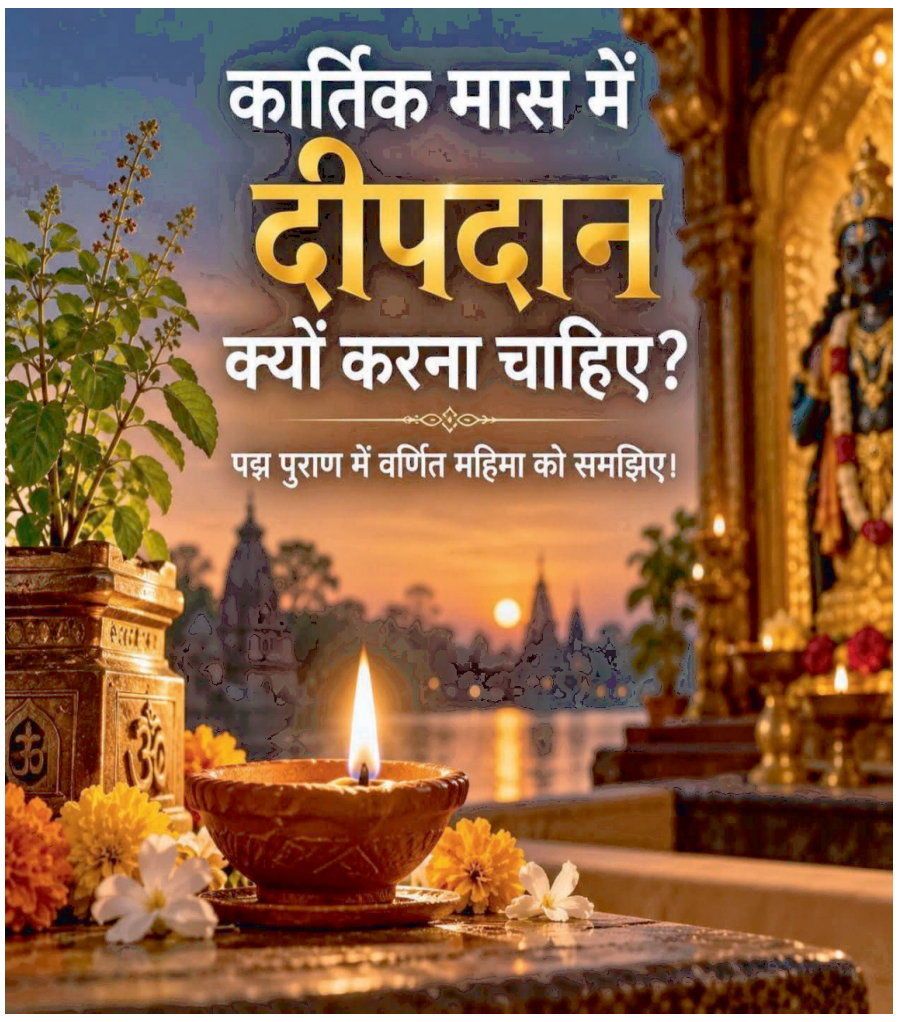
धन व करियर: दिन 7 आपकी महत्वाकांक्षी ऊर्जा को अधिक रणनीतिक बनाता है। विस्तार या प्रतिबद्धता से पहले कॉन्ट्रैक्ट, निवेश, टैक्स या व्यावसायिक जोखिम सावधानी से जांचें।
रिश्ते: भावनात्मक अनिश्चितता को नियंत्रण से हल नहीं किया जा सकता। निर्देश देने या निष्कर्ष निकालने से पहले सुनें और देखें।
सावधानी: गोपनीयता, शक्ति संघर्ष और व्यक्तिगत विषयों से बचने के लिए केवल काम में डूबने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: बल के बजाय रणनीति चुनें और एक महत्वपूर्ण निर्णय तथ्य के आधार पर लें।

मूलांक 9

धन व करियर: दिन 7 अगले अध्याय से पहले चिंतन को समर्थन देता है। शोध पूरा करें, देखें धन या ऊर्जा कहां व्यर्थ जा रही है और नई प्रतिबद्धता से पहले संसाधन सुरक्षित करें।
रिश्ते: शांत समय में पुरानी भावनाएं सामने आ सकती हैं। उन्हें समझ और उपचार के लिए उपयोग करें, पहले से सीख चुके विवाद को दोबारा खोलने के लिए नहीं।
सावधानी: भावनात्मक दूरी, अपराधबोध में देने और दूसरों का बोझ स्वयं उठाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक मानसिक बोझ छोड़ें और उससे मिली समझ अपने साथ रखें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes
Vediccodes - Your vibrations... our solutions

कार्तिक मास में दीपदान क्यों करना चाहिए?



परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

पद्म पुराण में वर्णित महिमा को समझिए !

* तुलसी जी के समीप दीपदान

तुलसी को भगवान विष्णु की परम प्रिय माना जाता है।

संध्या के समय तुलसी के समीप दीप जलाना अनेक हिंदू परिवारों की परंपरा है।

यह दीपदान भगवान के प्रति श्रद्धा, परिवार के मंगल और घर में सात्त्विक वातावरण बनाए रखने की भावना से किया जाता है।

ॐ

*** आकाशदीप का विशेष महत्त्व**

कार्तिक मास में आकाशदीप जलाने की परंपरा भगवान दामोदर की आराधना से जुड़ी हुई है।

विभिन वैष्णव परंपराओं में इसे पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रार्थना और मंगलकामना से भी जोड़ा जाता है।

आकाशदीप अर्पित करते समय भगवान से अपने पूर्वजों की सद्गति तथा परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जा सकती है।

* दीपदान करते समय एक बात याद रखें

पूजा में सबसे महत्त्वपूर्ण है श्रद्धा और भाव।

आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर दीप जला सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष दिखावे या महँगी सामग्री की आवश्यकता नहीं है।

पद्म पुराण के कार्तिक माहात्म्य में दीपदान की महिमा का वर्णन मिलता है। हालाँकि, इससे जुड़े प्रत्येक विशेष फल या नियम को किसी निशित श्लोक से जोड़ने से पहले मूल ग्रंथ का संदर्भदेखना चाहिए।

'मेरी दृष्टि में दीपदान का सबसे सुंदर' पक्ष यही है-

जैसे एक छोटा-सा दीपक अंधेरे में प्रकाश कर देता है, वैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा-सा ज्ञान, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा बहुत कुछ बदल सकते हैं।

कार्तिक मास 2026: कब से शुरू, कब समाप्त होगा? जानिए महत्व, व्रत-त्योहार और खास उपाय

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ महीना माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे देवताओं में भगवान विष्णु और नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, वैसे ही महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस महीने का संबंध भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और तुलसी जी से है।

कार्तिक मास 2026 कब से कब तक है?

पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है।

उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार:

- कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा प्रारंभ: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार सुबह 9:42 बजे से
- कार्तिक माह प्रारंभ (व्रत-नियम): 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार से (उदया तिथि के अनुसार)
- कार्तिक माह समाप्त: 24 नवंबर 2026, मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर

इस प्रकार कार्तिक मास कुल 29 दिन का रहेगा। इस दौरान कार्तिक स्नान 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक किया जाएगा।

> नोट: गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अमांत पंचांग मान्य है, वहां कार्तिक मास 10 नवंबर से 8 दिसंबर 2026 तक माना जाएगा।

कार्तिक मास का धार्मिक महत्व

पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में ही भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इसलिए इस महीने में की गई पूजा, स्नान और दीपदान का फल कई गुना मिलता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीपदान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मथुरा-वृंदावन, अयोध्या और काशी में कार्तिक मास की विशेष रौनक देखने को मिलती है।

कार्तिक मास 2026 के मुख्य व्रत-त्योहार

इसी पवित्र महीने में साल के सबसे बड़े पर्व आते हैं:

1. करवा चौथ - 29 अक्टूबर 2026
2. धनतेरस - 6 नवंबर 2026
3. नरक चतुर्दशी और दीपावली - 8 नवंबर 2026
4. गोवर्धन पूजा - 10 नवंबर 2026
5. भैया दूज - 11 नवंबर 2026
6. छठ पूजा - 15 नवंबर 2026
7. गोपाष्टमी और आंवला नवमी
8. देवउठनी एकादशी / प्रबोधिनी एकादशी - 20 नवंबर 2026
9. तुलसी विवाह
10. कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली - 24 नवंबर 2026

कार्तिक मास में क्या करें? खास उपाय

1. दीपदान: रोज सुबह और शाम तुलसी के पास और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। कार्तिक में दीपदान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है।
2. तुलसी पूजा: रोज तुलसी जी को जल अर्पित करें और परिक्रमा करें।
3. विष्णु-श्रीकृष्ण पूजन: रोज विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ और दामोदर अष्टकम का पाठ करें।
4. दान-पुण्य: इस महीने अन्न, वस्त्र, और आंवले का दान करना बहुत शुभ होता है।
5. नियम: इस महीने सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और झूठ, निंदा से बचें।



वृंदावन में शरद पूर्णिमा पर बाबा गोपाल दास की स्मृति में होगा भव्य संकीर्तन, चीर घाट पर सजेगा भक्ति का मंच

(डॉ गोपाल चतुर्वेदी)

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

वृंदावन (मथुरा)। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर वृंदावन के चीर घाट पर भव्य संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है।

आयोजकों के अनुसार यह उत्सव 25 अक्टूबर 2026, रात्रि 8 बजे से यमुना के किनारे, चीर घाट, वृंदावन में मनाया जाएगा। यह संकीर्तन बाबा गोपाल दास लघुसखी महाराज (सेवा कुंज वाले) की स्मृति में हो रहा है, क्योंकि बाबा गोपाल दास अब नहीं है।

यह कार्यक्रम महंत सुंदरी शरण महाराज के पावन सानिध्य में होगा।

भक्ति संध्या को और भी मधुर बनाने के लिए प्रसिद्ध भजन गायक रविन्दन शास्त्री, साहिल सांवरिया और हेमंत रमन अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे।

कार्यक्रम के आयोजक बाबा जमुना दास हैं, जबकि आयोजन सभी ठाकुर भक्तों द्वारा किया जा रहा है।



प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में झज्जर की उल्लेखनीय पहल

पर्यावरण संरक्षण के तहत जिला के गांव खेड़का गुर्जर में मौजूद देशवाल भट्टा कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सभी ईंट भट्ठे जिग-जैग तकनीक से संचालित, दूसरे जिलों के लिए बन रहा झज्जर अनुकरणीय मॉडल

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- प्रदूषण के हर स्त्रोत पर है प्रशासन की पैनी नजर
फील्ड मॉनिटरिंग और ड्रोन से होगी निगरानी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

झज्जर, 22 अक्टूबर*

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए झज्जर जिला प्रशासन व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध कार्यशैली के साथ आगे बढ़ रहा है। झज्जर जिले के गांव खेड़का गुर्जर स्थित देशवाल भट्टा कम्पनी प्रदूषण नियंत्रण में आधुनिक तकनीक का रोल मॉडल बना हुआ है वहीं जिला में स्थित अन्य 265 ईंट भट्ठों का जिग-जैग तकनीक से संचालन प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पहल है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह व्यवस्था अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय है। गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरमैन राजेश वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में झज्जर जिला प्रशासन द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, एसीएस शेखर विद्यार्थी व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों द्वारा वीसी में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की गई।

वीसी उपरांत डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि पराली जलाने, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं, वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।

डीसी ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को प्रभावी रूप से कार्य करना होगा। प्रदूषण के किसी भी स्त्रोत की अनदेखी नहीं की जाएगी और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित फील्ड मॉनिटरिंग के साथ जरूरत के अनुसार ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की सूचना मिलते ही क्विक रिस्पॉन्स टीमें तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ईंट भट्ठों में निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की नियमित जांच भी की जाए और तकनीक के प्रभावी संचालन के साथ नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जा रहे उपायों का प्रभाव तभी व्यापक होगा, जब तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ नियमित निगरानी और नियमों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाए। झज्जर में जिग-जैग तकनीक से संचालित ईंट भट्ठों की व्यवस्था को प्रदूषण नियंत्रण के व्यापक प्रयासों से जोड़ते हुए अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है।

पराली प्रबंधन पर जोर, किसानों को जागरूक करने के निर्देश*

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के



वैज्ञानिक और वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पराली जलाने की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। अधिकारी नियमित फील्ड विजिट करें और ग्राम पंचायतों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। पराली जलाने की घटना सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही भुवन एप और सीआरएम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के विकल्पों और योजनाओं का लाभ मिल सके।

औद्योगिक प्रदूषण से लेकर सड़क की धूल तक, हर स्त्रोत पर निगरानी*

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल पराली जलाने पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियां भी प्रदूषण बढ़ाती हैं। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और कमियों को समय रहते दूर करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों की नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए निर्धारित मानकों की पालना करवाई जाए। वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच की जाए तथा ठोस कचरे और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए।

हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बढ़ रही निगरानी, ड्रोन से भी रखी जा रही नजर*

डीसी ने प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड मॉनिटरिंग के साथ जरूरत के अनुसार ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए रहा है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले स्त्रोतों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें। किसी भी घटना की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और नियमानुसार कार्रवाई करे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी उपायों की नियमित समीक्षा की जाए। विभागीय समन्वय, समयबद्ध कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्तर पर अनदेखा न किया जाए।

यह रहे मौजूद*

बैठक में एडीसी जगनिवास, एसीपी अनिरुद्ध चौहान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ.सुनील श्योराण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ डॉ. सुनील कौशिक, डॉ. जगजीत सांगवान, एडीटीओ राजेश मलिक, एएफएसओ अमरजीत सिंह, नगर परिषद के ईओ दविंदर सिंह, तकनीकी अधिकारी डॉ. रोहित वत्स सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

गैर-अधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदारी करने से बचें नागरिक : डीसी

*- *जिला के गांव नंगला में संबंधित विभाग ने अधिसूचित किए खसरा नंबर**

झज्जर, 22 अक्टूबर डीसी वर्षा खांगवाल ने झज्जर जिलावासियों से आह्वान किया कि वे जिला की राजस्व सीमा में प्लाट खरीदने से पहले राजस्व, डीटीपी, शहरी निकाय सहित संबंधित विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना वैध लाईसेंस के किसी भी अवैध कॉलोनी में जमीन या प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें।

डीसी वर्षा खांगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के गांव नंगला में बिना लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी प्राप्त किए अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित करने की रिपोर्ट प्रशासन के संज्ञान में आई है। उन्होंने बताया कि गांव नंगला में मुसतिल / किला नंबर 39//16,17,40//20 , 11//14,15,16,17, 19//4,5,6,7 व 14//4,5,6,7 में कोई भी व्यक्ति जमीन की खरीदारी न करें।

उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि चिन्हित क्षेत्र में किसी प्रकार के बिजली कनेक्शन जारी ना किए जाएं।

डीसी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के विकसित की जा रही किसी भी कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, इंतकाल आदि) उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन न करें।

डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन से आहवान किया कि जमीन या प्लॉट की खरीद करने से पूर्व सम्बंधित विभाग से जानकारी अवश्य लेकर खरीद परोख्त करें।



समाधान शिविर जनसमस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम : एसडीएम



एसडीएम बादली विशाल कुमार ने उपमण्डल स्तरीय समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं

बादली, 22 अक्टूबर

आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बादली में एसडीएम विशाल कुमार की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एसडीएम विशाल कुमार ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया।

शिकायतों का जल्द समाधान करना प्रशासन का दायित्व

एसडीएम विशाल कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ सरलता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करवाना है, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में उनका निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने और उनका प्रभावी समाधान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस अवसर पर सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर आपातकालीन सेवाओं को लेकर प्रशासन सतर्क : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला नागरिक अस्पताल का किया निरीक्षण, जनरेटर सहित वैकल्पिक बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश

झज्जर, 22 अक्टूबर।

बिजली कर्मचारियों की 24 अक्टूबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आवश्यक जनसेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्था प्रबन्धन पर विशेष फोकस किया है। इसी क्रम में डीसी वर्षा खांगवाल ने गुरुवार की देर सायं जिला नागरिक अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी मरीजों के उपचार और आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान डीसी ने डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. कुलदीप सिंह से जिलाभर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में जनरेटर सहित बिजली के वैकल्पिक प्रबंधों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें।



आवश्यक सेवाओं का निर्बाध संचालन प्रशासन की प्राथमिकता*

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के दौरान आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बिजली आपूर्ति के साथ पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। विशेष रूप से अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं, मरीजों के उपचार और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

आमजन को असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन सतर्क*

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखना, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। इसके लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने और अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

जनसमस्याओं के स्थाई समाधान का आधार बन रहे समाधान शिविर : एडीसी

-जिलास्तरीय समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर,22 अक्टूबर।

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी सजगता व गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी मंच साबित हो रहे हैं। यह बात एडीसी जगनिवास ने सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जनसुनवाई के दौरान कही। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाना ही उद्देश्य

एडीसी ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाना है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहते हैं, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारी लंबित शिकायतों का आपसी समन्वय से तत्काल करें समाधान

एडीसी जगनिवास ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की लगातार निगरानी की जा रही है। अब तक प्राप्त अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया पर भी नियमित नजर रखें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन,परिवार पहचान पत्र से जुड़े मामले पहुंचे

समाधान शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़े मामलों को भी नागरिकों ने अधिकारियों के समक्ष रखा। एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई



मामलों में मौके पर ही आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया गया।

एडीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करें।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर सीटीएम ऋचु, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन पंचायती राज युद्धवीर सिंह, एमिनेंट पर्सन चुन्नी लाल सैनी और कष्ट निवारण समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

UP में अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी देना होगा शुल्क - अलग-अलग वाहनों के लिए तय हुआ यूजर चार्ज

ADTC संचालक के खाते में जाएगी पूरी राशि, शासन स्तर पर तैयारी पूरी - 20 जिलों के 32 केंद्रों पर लागू होगी व्यवस्था I 18 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट



रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र लखनऊ ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे आवेदकों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए बने ट्रैक के इस्तेमाल पर यूजर चार्ज लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 5bbb

पुष्टि और आधिकारिक स्रोत:

आधिकारिक बयान: राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सगीर अहमद अंसारी ने पुष्टि की है - "तीन वाहन श्रेणियों में ट्रैक यूजिंग चार्ज लिया जाएगा। इसकी राशि ADTC संचालक के खाते में जाएगी और व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी।"

- वर्तमान स्थिति: खबरों के अनुसार शासन स्तर पर इसे लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम राजपत्रित अधिसूचना / शासनादेश की तारीख अभी घोषित होना बाकी है। इसलिए यह प्रस्तावित व्यवस्था है, लागू होने की अंतिम तिथि की आधिकारिक पुष्टि परिवहन विभाग की वेबसाइट से करनी होगी।

मुख्य तथ्य और बिंदु:

1. कितना लगेगा यूजर चार्ज?
- दोपहिया वाहन: 50 रुपये प्रति टेस्ट
- हल्के मोटर वाहन (कार आदि): 100 रुपये प्रति टेस्ट
- भारी मोटर वाहन: 150 रुपये प्रति टेस्ट

2. पैसा कहां जाएगा?

प्रस्ताव के अनुसार यूजर चार्ज की पूरी राशि संबंधित प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (ADTC) के संचालक के खाते में जाएगी। उद्देश्य ट्रैक के रखरखाव और संचालन की लागत को पूरा करना बताया जा रहा है।

3. ADTC क्या है?

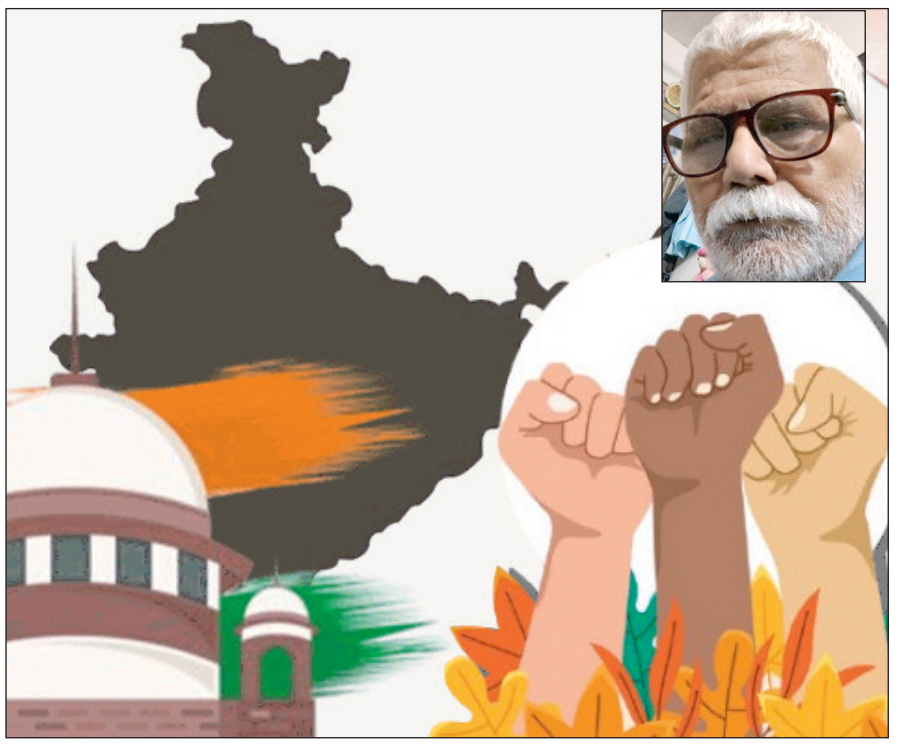
परिवहन विभाग ने बेहतर चालक तैयार करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ADTC स्थापित किए हैं। ये केंद्र निजी संचालकों के हाथों में हैं। प्रदेश के 20 जिलों में कुल 32 केंद्र काम कर रहे हैं। लखनऊ में काकोरी के उदितखेड़ा में एक केंद्र संचालित है।

4. मौजूदा सरकारी फीस कितनी है?
- लर्नर लाइसेंस: 350 रुपये
- स्थायी DL: 1000 रुपये
- कुल सरकारी फीस: 1350 रुपये
- दलालों के माध्यम से: 4000 से 6000 रुपये तक खर्च
- ADTC को इस नए चार्ज से प्रतिमाह औसतन तीन लाख रुपये की आमदनी का अनुमान है।

5. फेल होने पर क्या नियम?
- एक बार फेल होने पर 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट का मौका, नया स्लॉट लेना होगा।
- दो बार फेल होने पर ADTC से ड्राइविंग प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क 6000 रुपये निर्धारित है।

विस्तृत विश्लेषण - जनहित में सवाल: यह व्यवस्था दोधारी तलवार है। एक तरफ इससे टेस्ट ट्रैक की गुणवत्ता सुधरेगी, दूसरी तरफ आम आवेदक पर बोझ बढ़ेगा। मूल सवाल यह है कि जब सरकारी फीस 1350 रुपये है, तो प्राइवेट ADTC को सीधा पैसा देना क्या निजीकरण की ओर कदम है? साथ ही 6000 रुपये की अनिवार्य ट्रेनिंग का प्रावधान गरीब आवेदकों के लिए भारी पड़ सकता है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यूजर चार्ज का ऑडिट कैसे होगा।

आज़ादी की आड़, लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों का छलावा



लेखक शंकर देव तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार व चिंतक!

प्रस्तुतकर्ता: भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी'

बात अगर सच्ची सुनोगे, तभी कुछ सोचोगे।

यह पंक्तियाँ केवल एक रचना की शुरुआत नहीं, बल्कि समकालीन भारत के उस अंतःकरण की आवाज़ हैं, जो व्यवस्था के भीतर पनप रही अघोषित 'हिटलरी' और तानाशाही प्रवृत्तियों पर मंथन करने को मजबूर है।

हम सब गर्व से कहते हैं कि हम महान भारत देश के निवासी हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि आख़िर आज़ादी के इतने दशकों बाद भी हम आंतरिक रूप से टुकड़ों में क्यों बंटे हुए हैं? हम एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में वैचारिक और सामाजिक तौर पर एक क्यों नहीं हो पाए? विडंबना देखिए कि आज भी आम नागरिक की मौलिक पहचान असमंजस के भंवर में है। जिस आम जनता को अपने मौलिक अधिकारों का रक्षक होना चाहिए था, वह आज भी अपने बुनियादी हकों से अनभिज्ञ है। अमीर और गरीब (राजा और रंक) के बीच की खाई पाटने का दम भरने वाला हमारा लोकतंत्र, आज बिना वास्तविक अधिकारों के एक ढांचा मात्र बनकर रह गया है।

सच तो यह है कि आरक्षण की राजनीति और निरंकुश आज़ादी की आड़ में आज जन-तंत्र (लोक-तंत्र) को सत्ता के गलियारों में गिरवी रख दिया गया है। जो शेष भारत बचा था, उसे पूरी तरह से स्वार्थी राजनीति के रंग में रंग दिया गया है। हमारे नीति-निर्माताओं ने कभी इस देश को स्वर्ग बनाने की कल्पना के साथ नियम और संविधान गढ़े थे। लेकिन आचरण में उन नियमों को भुलाकर जनता को नर्क जैसी विसंगतियों में ढकेल दिया गया, जबकि सत्ता की मलाई चाटने वाले हुक्मरान खुद को 'देवता' मानकर वातानुकूलित महलों में बस गए।

इतिहास गवाह है कि यहाँ आदमी ने कभी दूसरे आदमी को इंसानियत के नाते खुलकर जीने और पनपने नहीं दिया। रही-सही कसर राजनीति ने पूरी कर दी, जो अब जननीति न रहकर 'कालनीति' बन चुकी है। इस कालनीति ने समाज में कभी कोई नेक काम अमली जामा नहीं पहनने दिया।

आज की शासन व्यवस्था का अघोषित नारा यही बन चुका है कि 'आज़ादी की आड़ में जनता जाए भाड़ में'। नीतियां जनहित के नाम पर बनती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल राजनीति की आड़ में खुद के हित साधने के लिए होता है। सरकारें पूरे दंभ और शान से चल रही हैं, जबकि जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायिका जैसे हाशिए पर डाल दी गई है। लोकतंत्र के इस आवरण में आज आम जनता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है।

आज हिंदुस्तान में 'मौलिक अधिकारों' की बातें करना महज़ एक छलावा और धोखा प्रतीत होता है। यह आलेख इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए एक विशेष मिशन की ओर इशारा करता है—नैतिकता के पुनरुत्थान का मिशन। जब तक देश का आम नागरिक राजनीति के इस छलावे को नहीं समझेगा और अपने नैतिक दायित्वों को पहचानकर एकजुट नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का असली सूरज नहीं उगेगा। अब समय आ गया है कि हम इस 'राजनीतिक कालनीति' के ख़िलाफ़ अपनी सामूहिक चेतना को जगाएं!!

राउरकेला के डेली मार्केट में कथित अवैध निर्माण पर सवाल, निगम और विकास प्राधिकरण की निगरानी कठघरे में



मुख्य बाजार क्षेत्र में तेजी से उठ रही इमारत, उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने की जानकारी; गरीबों पर सख्ती और प्रभावशाली लोगों पर नरमी के आरोप

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

राउरकेला में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर नगर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। राउरकेला डेली मार्केट जैसे शहर के व्यस्त और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में कथित तौर पर विवादित जमीन पर तेजी से हो रहे भवन निर्माण ने राउरकेला महानगर निगम और राउरकेला विकास प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित जमीन पर कब्जे और निर्माण को लेकर विवाद है तथा मामला उच्च न्यायालय में लंबित बताया जा रहा है। इसके बावजूद निर्माण कार्य आगे बढ़ने के आरोप हैं। हालांकि, न्यायालय में लंबित मामले की वास्तविक स्थिति, किसी अंतरिम रोक के आदेश और जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। यदि निर्माण पर कोई प्रभावी न्यायिक रोक लागू है, तो उसके बावजूद काम जारी रहना गंभीर विषय होगा और संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र में यदि कोई निर्माण लगातार आगे बढ़ रहा है, तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही है? क्या निर्माण की अनुमति, भूमि की स्थिति और स्वीकृत नक्शे की जांच की गई है? यदि निर्माण नियमों के अनुरूप है, तो प्रशासन को दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?

स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी उठता रहा है कि अतिक्रमण के मामलों में कमजोर और गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई अधिक तेजी से होती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामलों में विभागीय तत्परता दिखाई नहीं देती। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि प्रशासन की कार्रवाई पर पक्षपात का संदेह दूर हो सके।

राउरकेला महानगर निगम और विकास प्राधिकरण के लिए यह केवल एक निर्माण का मामला नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन और प्रशासनिक विश्वसनीयता की परीक्षा है। अधिकारियों को स्थल निरीक्षण, निर्माण की अनुमति, भूमि संबंधी अभिलेखों और न्यायालय के आदेशों की स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए।

शहर के बीचोंबीच उठ रहे इन सवालों का जवाब केवल औपचारिक कार्रवाई से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और नियमों के निष्पक्ष पालन से ही मिलेगा।

ओडिशा में शराब दुकानों को लेकर बढ़ीं शिकायतें, आबकारी विभाग ने कार्रवाई के लिए आयुक्त को भेजे दस्तावेज

अवैध बिक्री, एमआरपी से अधिक वसूली और जहरीली शराब की आशंकाओं पर उठे सवाल; सुंदरगढ़ के कुआरमुंडा में स्थानीय आदिवासियों के विरोध का भी उल्लेख

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र भुवनेश्वर/राउरकेला





ओडिशा में शराब की दुकानों के संचालन, उनके स्थान निर्धारण और कथित अनियमितताओं को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही शिकायतों पर राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर कदम बढ़ाया है। विभाग ने अलग-अलग व्यक्तियों एवं संगठनों की ओर से प्राप्त शिकायतों, आपत्तियों और आरोपों से संबंधित दस्तावेज आबकारी आयुक्त, ओडिशा को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

22 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी पत्र संख्या 5356/Ex. में अवर सचिव काली चरण मिश्रा ने आबकारी आयुक्त को शिकायतों से संबंधित अनुलग्नक सौंपते हुए कार्रवाई रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सके। पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और संबंधित अन्य अधिकारियों को भी भेजे जाने का उल्लेख है।

सरकारी दस्तावेज के अनुलग्नक-डी में दर्ज शिकायतें आबकारी व्यवस्था के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इनमें बालेश्वर जिले के डुबशाही गांव में कथित अवैध शराब दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग, नकली अथवा जहरीली शराब के कारोबार की आशंका और विभिन्न जिले की आईएमएफएल दुकान में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ऊपर शराब बेचने तथा अतिरिक्त रुपये वसूलने की शिकायत शामिल है।

इसी सूची में सुंदरगढ़ जिले के बिरमित्रपुर स्थित शराब निर्माण केंद्र की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग भी प्रमुखता से दर्ज है। सबसे महत्वपूर्ण मामला कुआरमुंडा में आउट स्टिल शराब दुकान की अनुमति और उसके कथित संचालन स्थल को लेकर है। दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय आदिवासी निवासियों ने 14 अक्टूबर को विरोध दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप है कि दुकान निर्धारित भूखंड के बजाय दूसरे भूखंड पर संचालित की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने स्थल का सीमांकन कर कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की है।

इसके अलावा कई और शहर के कुछ शराब दुकानों को बंद करने अथवा स्थानांतरित करने और दुकान के प्रस्तावित स्थानांतरण पर भी आपत्तियां दर्ज हैं।

हालांकि, इन शिकायतों का सरकारी दस्तावेज में उल्लेख होना आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। अब निगाहें आबकारी विभाग की जांच, कार्रवाई रिपोर्ट और इस बात पर टिकी हैं कि शिकायतों पर धरातल पर कितना प्रभावी कदम उठाया जाता है।

भाजपा किसान मोर्चा कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अमित शाह का जन्मदिन

डॉ. मनीष पंकज मिश्रा ने अमित शाह के संगठनात्मक नेतृत्व और राष्ट्रसेवा को बताया कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत



गयाजी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यालय, गयाजी में हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी डॉ. मनीष पंकज मिश्रा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अमित शाह को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की।

इस अवसर पर डॉ. मनीष पंकज मिश्रा ने अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनका कुशल संगठनात्मक नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण देशभर के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व, दूरदर्शिता और कार्यशैली ने भारतीय जनता पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान की है। उनका जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन के प्रति निष्ठा और जनकल्याण के संकल्प का प्रतीक है। सभी कार्यकर्ताओं की कामना है कि उनके मार्गदर्शन में देश विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि गयाजी की पावन धरती पर भगवान विष्णु एवं शक्तिपीठ मां मंगला गौरी से प्रार्थना है कि अमित शाह को उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करें, ताकि वे निरंतर राष्ट्रसेवा करते हुए भारत को विकास एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें।

इस अवसर पर ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, श्याम किशोर मिश्रा, आकाश कुमार, राजू मिश्रा, दीपक मिश्रा, डॉ. मिहिर कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मंटू कुमार, बबलू गुप्ता सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में गणित: एक ऐसा कौशल जिसे खोना हमारे लिए संभव नहीं





डॉ. विजय गर्ग
रिटायर्ड प्रिंसिपल |
एमिनेंट साइंटिस्ट

अनेक विद्यार्थियों के लिए गणित का अर्थ सूत्र, समीकरण, परीक्षाएँ और संख्यात्मक प्रश्न होते हैं। लेकिन इसका वास्तविक महत्त्व इन गतिविधियों से कहीं अधिक व्यापक है। गणित तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता, पैटर्न पहचानने, समस्याओं को हल करने और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने की योग्यता विकसित करता है। जब विद्यार्थी किसी गणितीय समस्या को हल करते हैं, तो वे आवश्यक जानकारी पहचानना, विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध समझना, अलग-अलग तरीकों पर विचार करना और अपने उत्तरों की जाँच करना सीखते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन, कार्य, शिक्षा और समस्याओं को हल करने के तरीकों में तेजी से बदलाव ला रही है। वॉयस असिस्टेंट और बुद्धिमान रोबोट से लेकर चिकित्सा निदान, वित्तीय पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान तक, AI प्रणालियाँ ऐसे अनेक कार्य करने में सक्षम हो रही हैं, जिनमें पहले काफी मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती थी। वे जटिल समीकरणों की गणना कर सकती हैं, विशाल मात्रा में आँकड़ों का विश्लेषण कर सकती हैं और कुछ ही सेकंड में गणितीय समस्याओं को हल कर सकती हैं। लेकिन तकनीकी प्रगति के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: यदि मशीनें इतनी कुशलता से गणना कर सकती हैं, तो विद्यार्थियों के लिए गणित सीखना क्यों आवश्यक है?

इसका उत्तर सरल है। गणित केवल गणना करने का विषय नहीं है। यह सोचने, तर्क करने, सूचनाओं का विश्लेषण करने और दुनिया को समझने का एक माध्यम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में गणित की शिक्षा का महत्त्व कम नहीं हो रहा, बल्कि पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है।

संख्याओं से आगे गणित का महत्त्व

अनेक विद्यार्थियों के लिए गणित का अर्थ सूत्र, समीकरण, परीक्षाएँ और संख्यात्मक प्रश्न होते हैं। लेकिन इसका वास्तविक महत्त्व इन गतिविधियों से कहीं अधिक व्यापक है। गणित तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता, पैटर्न पहचानने, समस्याओं को हल करने और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने की योग्यता विकसित करता है।

जब विद्यार्थी किसी गणितीय समस्या को हल करते हैं, तो वे आवश्यक जानकारी पहचानना, विभिन्न तथ्यों के बीच संबंध समझना, अलग-अलग तरीकों पर विचार करना और अपने उत्तरों की जाँच करना सीखते हैं। ये क्षमताएँ विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित लगभग हर क्षेत्र में उपयोगी हैं।

AI उत्तर दे सकता है, लेकिन उन उत्तरों की तार्किकता, शुद्धता और उपयोगिता को परखने के लिए गणितीय समझ आवश्यक है। इस आधार के बिना विद्यार्थी किसी गलत उत्तर को भी केवल इसलिए सही मान सकते हैं, क्योंकि वह किसी उन्नत तकनीकी प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव है गणित

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भले ही बुद्धिमान दिखाई देती हो, लेकिन इसकी अधिकांश क्षमताओं का आधार गणितीय सिद्धांत हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियाँ बीजगणित, कलन, प्रायिकता, सांख्यिकी और रैखिक बीजगणित जैसी अवधारणाओं पर निर्भर करती हैं।

उदाहरण के लिए, AI प्रणालियाँ आँकड़ों में पैटर्न पहचानने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करती हैं। प्रायिकता विभिन्न परिणामों की संभावना का अनुमान लगाने में सहायता करती है, जबकि कलन और रैखिक बीजगणित अनेक मशीन लर्निंग मॉडलों के प्रशिक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन सिद्धांतों की समझ विद्यार्थियों को AI के कार्य करने के तरीके को जानने में सहायता देती है। वे इसे किसी रहस्यमय डिजिटल उपकरण के बजाय वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीक के रूप में समझ सकते हैं।

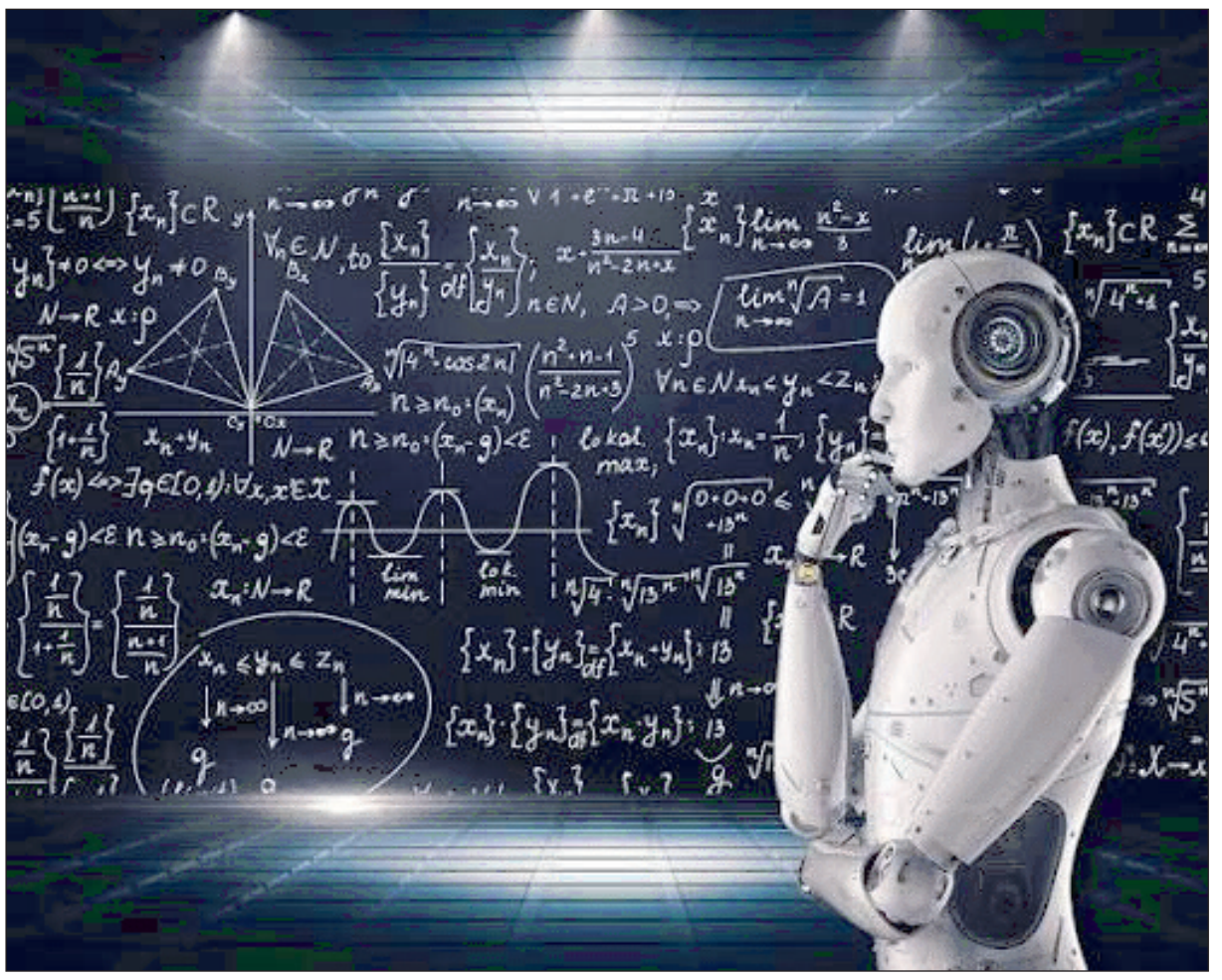
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए AI शोधकर्ता बनना या उच्च स्तरीय गणित में विशेषज्ञता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। फिर भी आधुनिक तकनीक को समझने, उसके परिणामों का मूल्यांकन करने और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए बुनियादी गणितीय ज्ञान लगातार अधिक आवश्यक होता जा रहा है।

कैलकुलेटर गणितीय चिंतन का विकल्प नहीं

कैलकुलेटर और कंप्यूटर दशकों से गणनाएँ करते आ रहे हैं। उनकी उपलब्धता ने गणित को समझने की आवश्यकता समाप्त नहीं की। इसी प्रकार AI कुछ समस्याओं को हल करने में लगने वाला समय कम कर सकता है, लेकिन यह समझना अब भी जरूरी है कि कौन-सी समस्या हल करनी है, कौन-सी विधि उपयुक्त है और प्राप्त उत्तर तर्कसंगत है या नहीं।

कल्पना कीजिए कि कोई विद्यार्थी AI से एक समीकरण हल करने के लिए कहता है। उसे सही उत्तर मिल सकता है, लेकिन मूल अवधारणाओं की समझ न होने पर वह गलती पहचानने, उसी विधि को किसी नई परिस्थिति में लागू करने या समाधान के पीछे का तर्क समझाने में असमर्थ हो सकता है।

वास्तविक खतरा केवल यह नहीं है कि AI विद्यार्थियों की क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है। खतरा यह भी है कि तैयार उत्तरों पर अत्यधिक निर्भरता स्वतंत्र चिंतन की आदत को कमजोर कर सकती है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य



तकनीक के माध्यम से गणितीय समझ को मजबूत करना होना चाहिए, न कि सीखने के लिए आवश्यक मानसिक प्रयास को समाप्त करना।

गणित विकसित करता है आलोचनात्मक चिंतन

AI द्वारा उत्पन्न जानकारी हमेशा सही नहीं होती। कभी-कभी यह भ्रामक आँकड़े, गलत गणनाएँ और ऐसी व्याख्याएँ प्रस्तुत कर सकता है जो सुनने में विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन उनमें त्रुटियाँ होती हैं। गणितीय ज्ञान लोगों को ऐसे परिणामों पर प्रश्न उठाने और उनके पीछे उपलब्ध प्रमाणों की जाँच करने में सहायता करता है।

आज चार्ट, सर्वेक्षण, रैंकिंग और संख्यात्मक दावों की भरमार है। ऐसे समय में सांख्यिकीय साक्षरता विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो गई है। नागरिकों को सहसंबंध और कारण-परिणाम के अंतर को समझना, प्रतिशत की सही व्याख्या करना, संभावनाओं का आकलन करना और यह पहचानना आना चाहिए कि आँकड़ों को किस प्रकार चुनिंदा ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, कोई भ्रामक विज्ञापन बहुत बड़ी प्रतिशत वृद्धि का दावा कर सकता है, लेकिन वास्तविक शुरुआती आँकड़ा नहीं बताता। इसी प्रकार कोई जनमत सर्वेक्षण अपने नमूने के आकार या सर्वेक्षण की पद्धति की जानकारी दिए बिना परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। गणित की अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति ऐसी कमजोरियों को पहचानने में अधिक सक्षम होता है।

इस प्रकार गणित केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि जागरूक और विवेकपूर्ण नागरिक बनने का व्यावहारिक साधन भी है।

गणित की शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता

AI का बढ़ता प्रभाव गणित पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। पारंपरिक कक्षाओं में कभी-कभी सूत्रों को याद करने और एक ही प्रकार के प्रश्न बार-बार हल करने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। अभ्यास और बुनियादी कौशल आवश्यक हैं, लेकिन इनके साथ अवधारणाओं की स्पष्ट समझ, तार्किक चिंतन और वास्तविक जीवन में गणित के उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए।

शिक्षक AI उपकरणों की सहायता से अतिरिक्त व्याख्याएँ दे सकते हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न तैयार कर सकते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं और विद्यार्थियों को किसी समस्या के विभिन्न समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दृश्य उदाहरण, सिमुलेशन और संवादात्मक गतिविधियाँ कठिन गणितीय अवधारणाओं को समझना आसान बना सकती हैं।

हालाँकि, तकनीक को शिक्षक का सहयोगी बनना चाहिए, उसका विकल्प नहीं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करना, अपने तर्क की व्याख्या करना, उत्तर का अनुमान लगाना और समाधान की जाँच करना सीखना चाहिए। मूल्यांकन में केवल अंतिम उत्तर के बजाय समझ और अवधारणाओं को नई परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

विद्यालयों को यह भी सिखाना चाहिए कि AI की सहायता कब उपयोगी है और किन परिस्थितियों में स्वतंत्र प्रयास आवश्यक है। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ-साथ बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा।

प्रत्येक बच्चे के लिए गणित को सुलभ बनाना

गणित का भय आज भी सीखने में एक बड़ी बाधा है। कई बच्चे कुछ अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होने पर स्वयं को गणित में कमजोर मानने लगते हैं। ऐसी धारणाएँ उनके आत्मविश्वास को नुकसान पहुँचा सकती हैं और उनकी वास्तविक क्षमताओं के विकास में बाधा बन सकती हैं।

शिक्षकों और अभिभावकों को गलतियों को असफलता मानने के बजाय जिज्ञासा, धैर्य और नियमित अभ्यास को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने, बिना किसी डर के प्रश्न पूछने और गणित को खरीदारी, बजट बनाने, मापने, खेलों तथा दैनिक जीवन के आँकड़ों से जोड़ने के अवसर मिलने चाहिए।

AI आधारित शिक्षण मंच विशेष रूप से उन विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर भी डिजिटल उपकरणों, विश्वसनीय इंटरनेट और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों तक सभी की समान पहुँच नहीं है। विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी प्रगति शिक्षा में असमानता को और न बढ़ाए।

भविष्य के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना

भविष्य के रोजगार क्षेत्र में उन लोगों की माँग बढ़ेगी जो तकनीकी दक्षता को मानवीय विवेक के साथ जोड़ सकें। गणित डेटा विज्ञान, इंजीनियरिंग, वित्त, चिकित्सा, पर्यावरण अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और अनेक उभरते क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऐसे व्यापक कौशल भी विकसित करता है जो तकनीक और रोजगार के स्वरूप बदलने के बाद भी उपयोगी बने रहते हैं।

विद्यार्थियों को गणना की गति में मशीनों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें मशीनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना सीखना चाहिए और साथ ही प्रश्न तैयार करने, परिणामों की व्याख्या करने तथा उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

AI के युग में गणित की शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए: विद्यार्थियों को केवल उत्तर प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह समझना भी सिखाया जाए कि उत्तर सही क्यों है और उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणनाएँ कर सकती है, पैटर्न पहचान सकती है और जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकती है। लेकिन इन क्षमताओं का सार्थक उपयोग मानवीय समझ, विवेक और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। गणित इन तीनों के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है।

जैसे-जैसे AI अधिक शक्तिशाली होगा, गणितीय चिंतन की क्षमता विद्यार्थियों को विश्वसनीय जानकारी और भ्रामक दावों के बीच अंतर करने, नई समस्याओं को हल करने और तकनीक-आधारित समाज में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में सहायता करेगी।

हमें गणित केवल इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए कि परीक्षाओं में इसकी आवश्यकता होती है या कुछ व्यवसायों में इसका उपयोग होता है। हमें इसे इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह लोगों को स्पष्ट रूप से सोचने, समझदारी से प्रश्न पूछने और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है।

AI के युग में वास्तविक लाभ केवल उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके पास सबसे उन्नत मशीनों तक पहुँच है, बल्कि उन लोगों को मिलेगा जो उनके उत्तरों पर प्रश्न उठाना, उनका मूल्यांकन करना और उनका सही उपयोग करना जानते हैं। गणित एक ऐसा कौशल है जिसे खोना हमारे लिए संभव नहीं है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य | प्रख्यात शिक्षाविद्
ऑनलाइन पत्रिका
FNBWorld.com
अकादमिक संपादक

अंग्रेज़ी से आगे विज्ञान: अपनी मातृभाषा में सीखने का महत्व

डॉ. विजय गर्ग

विज्ञान आधुनिक सभ्यता की नींव है। यह हमें प्रकृति को समझने, ब्रह्मांड का अन्वेषण करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने, तकनीक विकसित करने और दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करता है। लेकिन विज्ञान को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा काफी हद तक यह निर्धारित करती है कि विद्यार्थी वैज्ञानिक अवधारणाओं को कितनी आसानी से समझ पाते हैं। भारत सहित अनेक देशों में अंग्रेज़ी को वैज्ञानिक शिक्षा और व्यावसायिक सफलता से जोड़कर देखा जाता है। यद्यपि अंग्रेज़ी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संवाद की एक महत्वपूर्ण भाषा है, फिर भी अपनी मातृभाषा में विज्ञान सीखने से ज्ञान अधिक सुलभ, अर्थपूर्ण और समावेशी बन सकता है।

विज्ञान शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परिभाषाओं, समीकरणों और वैज्ञानिक शब्दावली को याद करना नहीं है। इसका उद्देश्य जिज्ञासा, तार्किक चिंतन, अवलोकन, प्रयोग करने की क्षमता और प्रश्न पूछने की आदत विकसित करना है। जब विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम की भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो उनका ध्यान वैज्ञानिक विचारों को समझने के बजाय अपरिचित शब्दों के अर्थ जानने में लग जाता है। परिचित भाषा में विज्ञान पढ़ाने से यह बाधा कम होती है और विद्यार्थी विषय की मूल अवधारणाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

रटने से पहले समझना आवश्यक

बच्चे विद्यालय जाने से पहले ही अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। वे वर्षा को देखते हैं, ऋतुओं में होने वाले बदलावों को महसूस करते हैं, पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता हुआ क्यों दिखाई देता है। इन अनुभवों को सामान्यतः उसी भाषा में समझा और व्यक्त किया जाता है, जो घर में बोली जाती है। जब विज्ञान की शिक्षा इसी परिचित भाषाई आधार पर विकसित होती है, तो जटिल अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है।

उदाहरण के लिए, कपड़ों के सूखने से वाष्पीकरण, ठंडे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें बनने से संघनन और किसी फल के नीचे गिरने से गुरुत्वाकर्षण को समझाया जा सकता है। जब विद्यार्थी इन अनुभवों पर अपनी समझ की भाषा में चर्चा करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन जाती है। परिचित शब्द कक्षा के ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं और बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

जो विद्यार्थी किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनी मातृभाषा में समझ लेता है, वह धीरे-धीरे उसकी औपचारिक शब्दावली अंग्रेज़ी या किसी अन्य भाषा में भी सीख सकता है। पहले अवधारणा की स्पष्ट समझ विकसित होनी चाहिए और उसके बाद तकनीकी शब्दावली को व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाना चाहिए।

भारत की भाषाई विविधता: एक मूल्यवान संसाधन

भारत असाधारण भाषाई विविधता वाला देश है। पंजाबी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, ओड़िया, असमिया और अनेक अन्य भाषाओं में समृद्ध सांस्कृतिक ज्ञान तथा दुनिया को समझने के विशिष्ट दृष्टिकोण मौजूद हैं। इस विविधता को बाधा मानने के बजाय शिक्षा के एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा के शुरुआती वर्षों में, जहाँ तक संभव हो, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि बच्चे अक्सर उस भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, जिससे वे परिचित होते हैं।

हालाँकि, इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सुविचारित योजना आवश्यक है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें, वैज्ञानिक शब्दकोश, प्रयोगशाला पुस्तिकाएँ, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजिटल शैक्षिक सामग्री विकसित की जानी चाहिए। केवल अनुवाद करना पर्याप्त नहीं है। शैक्षिक सामग्री वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक तथा विद्यार्थियों की आयु और सीखने के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।



मातृभाषा और वैज्ञानिक चिंतन

विज्ञान प्रश्न पूछने, तर्क करने और प्रयोग करने से आगे बढ़ता है। विद्यार्थियों में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वे पूछ सकें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, कोई मशीन कैसे काम करती है या किसी वैज्ञानिक दावे के समर्थन में क्या प्रमाण हैं। यदि वे भाषाई गलतियाँ करने से डरते हैं, तो अपने विचार व्यक्त करने में झिझक सकते हैं।

परिचित भाषा में सीखने से कक्षा का वातावरण अधिक सहज बन सकता है। विद्यार्थी अंग्रेज़ी पर अपनी सीमित पकड़ के कारण अनावश्यक रूप से बाधित हुए बिना अपने अवलोकनों पर चर्चा कर सकते हैं, परिकल्पनाएँ समझा सकते हैं और तर्कों की जाँच कर सकते हैं। शिक्षक भी उनकी गलत धारणाओं को आसानी से पहचानकर गहन विचार-विमर्श को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि मातृभाषा में शिक्षा देने से अपने आप बेहतर परिणामों की गारंटी मिल जाती है। शिक्षण की गुणवत्ता, प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, कक्षा के संसाधन और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रमुख लाभ अनावश्यक भाषाई बाधाओं को कम करना और विषय की समझ को मजबूत बनाना है।

अंग्रेज़ी का महत्व भी बना रहेगा

भारतीय भाषाओं में विज्ञान शिक्षा का समर्थन करने का अर्थ अंग्रेज़ी का विरोध करना नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी अंतरराष्ट्रीय शोधपत्रों, वैज्ञानिक पत्रिकाओं, उच्चस्तरीय पाठ्यपुस्तकों, सम्मेलनों और वैश्विक व्यावसायिक अवसरों तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी परिचित भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी वैज्ञानिक जानकारी समझने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

द्विभाषी या बहुभाषी शिक्षा इस दिशा में प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकती है। शिक्षक पहले मातृभाषा में किसी अवधारणा को समझा सकते हैं, फिर उससे संबंधित वैज्ञानिक शब्दावली अंग्रेज़ी में बता सकते हैं और विद्यार्थियों को दोनों भाषाओं में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तकों में क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के समानार्थी वैज्ञानिक शब्द शामिल किए जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, पंजाबी में प्रकाश संश्लेषण पढ़ने वाला विद्यार्थी पहले इस प्रक्रिया को अपनी भाषा में समझ सकता है और फिर उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक अंग्रेज़ी शब्दावली सीख सकता है। इससे उसकी वैज्ञानिक समझ और अंतरराष्ट्रीय ज्ञान तक पहुँचने की भाषाई क्षमता दोनों विकसित होती हैं।

उद्देश्य विद्यार्थियों के अवसरों को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उन्हें किसी एक भाषा तक सीमित करना।

तकनीक भाषाई दूरी कम कर सकती है

डिजिटल तकनीक विज्ञान की शिक्षा को अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराने के नए अवसर प्रदान करती है। ऑनलाइन व्याख्यान, एनिमेशन आधारित स्पष्टीकरण, शैक्षिक ऐप, शोध के अनुवादित सारांश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शिक्षण उपकरण विद्यार्थियों को कठिन अवधारणाएँ समझने में सहायता कर सकते हैं।

ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में निःशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों से विशेष लाभ मिल सकता है। हालाँकि, डिजिटल अनुवादों की सावधानीपूर्वक जाँच आवश्यक है, क्योंकि गलत वैज्ञानिक शब्दावली भ्रम पैदा कर सकती है। सामग्री का व्यापक उपयोग करने से पहले शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों द्वारा उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सरकारों, विश्वविद्यालयों, प्रकाशकों और तकनीकी संस्थानों को मिलकर सुलभ बहुभाषी वैज्ञानिक सामग्री विकसित करनी चाहिए। निःशुल्क शैक्षिक संसाधन विद्यालयों को महँगी पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ सामग्री की कमी दूर करने में भी मदद कर सकते हैं।

शिक्षक: भाषाओं के बीच सेतु

स्थानीय भाषाओं को वैश्विक वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें मातृभाषा और अंग्रेज़ी में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे वैज्ञानिक सिद्धांत समझाने के लिए स्थानीय कृषि, घरेलू गतिविधियों, पारंपरिक शिल्प और प्राकृतिक वातावरण से जुड़े उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं।

पंजाब में मिट्टी, सिंचाई, फसलों की वृद्धि और मौसम पर चर्चा करके विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों को जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। ऐसे उदाहरण शिक्षा को जीवन से जोड़ते हैं और विद्यार्थियों को अपने आसपास की दुनिया में वैज्ञानिक सिद्धांतों की पहचान करना सिखाते हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को अवधारणाएँ स्पष्ट रूप से समझाने, उपयुक्त वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करने और मातृभाषा के साथ-साथ विद्यार्थियों की अंग्रेज़ी में वैज्ञानिक दक्षता विकसित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

समावेशी वैज्ञानिक भविष्य की ओर

भाषा ज्ञान के द्वार खोलने का माध्यम होनी चाहिए, न कि उसके रास्ते की बाधा। किसी गाँव में रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी को भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान या खगोल विज्ञान समझने के उतने ही अवसर मिलने चाहिए, जितने किसी शहरी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थी को मिलते हैं। वैज्ञानिक क्षमता केवल किसी विशेष भाषा में दक्षता पर नहीं, बल्कि जिज्ञासा, तर्कशक्ति, परिश्रम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच पर निर्भर करती है।

भारत की वैज्ञानिक प्रगति तब और मजबूत होगी, जब अधिक लोग वैज्ञानिक खोजों को समझ सकेंगे, प्रमाणों का मूल्यांकन कर सकेंगे और ज्ञान का उपयोग स्थानीय समस्याओं के समाधान में कर सकेंगे। मातृभाषा में विज्ञान सीखने से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, बुनियादी समझ मजबूत हो सकती है और युवाओं को वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता न तो अंग्रेज़ी को छोड़ना है और न ही भारतीय भाषाओं के महत्व को कम आँकना। आवश्यकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें विभिन्न भाषाएँ एक-दूसरे की पूरक बनें और प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीख सके।

विज्ञान संपूर्ण मानवता की साझा धरोहर है, किसी एक भाषा की संपत्ति नहीं। जब वैज्ञानिक ज्ञान विद्यार्थियों तक उस भाषा में पहुँचता है, जिसे वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं, तो वह केवल पाठ्यपुस्तक में छपी जानकारी नहीं रह जाता। वह स्वतंत्र चिंतन, नवाचार और सामाजिक प्रगति का साधन बन जाता है।

विज्ञान शिक्षा का भविष्य इसी में है कि ज्ञान को हर भाषा में, हर व्यक्ति के लिए समझने योग्य बनाया जाए।

झुर्रियां चेहरे पर आती हैं, दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती - लास्ट बेंच वाली दोस्ती

सत्तर साल की उम्र में तीन घंटे की हंसी ने बीमारियां भुला दीं — बुजुर्गों के लिए दोस्त ही सबसे बड़ी दवा हैं

परिवहन विशेष समाचार पत्र - जीवनशैली विशेष - संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक | पिंकी कुंडू, सह संपादक

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना स्वाभाविक है, लेकिन दिल में बसी दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। जीवन की भागदौड़, जिम्मेदारियों और समय के लंबे अंतराल के बाद जब पुराने दोस्त मिलते हैं, तो उम्र की सीमाएं टूट जाती हैं और इंसान फिर अपने बचपन में लौट जाता है। सत्तर वर्ष की उम्र में छह पुराने दोस्तों की तीन घंटे की मुलाकात इसी सच्चाई को उजागर करती है कि हंसी, अपनापन और पुरानी यादें जीवन को नई ऊर्जा दे सकती हैं। आज जब अकेलापन बुजुर्गों के जीवन की एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, तब बचपन की दोस्ती केवल भावनात्मक सहारा ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। 'लास्ट बेंच वाली दोस्ती' की यह कहानी बताती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर खुश रहने के लिए केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि ऐसे दोस्त भी चाहिए, जिनके साथ हम बिना किसी औपचारिकता के फिर से बच्चे बन सकें।

तथ्य — कहानी स्वरूप

- पात्रः छह दोस्त, सभी सत्तर से ऊपर, दशकों बाद मिले

- स्थानः एक रेस्तरां, वेटर ने कहा — ₹शांत कोना चाहिए?"

- जवाबः "नहीं... क्या लास्ट बेंच है?"

- तीन घंटे में: तीन कंपनियों का मालिक फिर से होमवर्क न करने वाला लड़का बन गया, मशहूर सर्जन टिफिन चोर, कर्नल गणित के सवाल पर रोने वाला बच्चा, टॉपर आज भी बोर्ड परीक्षा का सपना देखता है

- निष्कर्षः तीन घंटे तक किसी ने नहीं पूछा — कितना पैसा, कौन सी गाड़ी, कौन सी बीमारी, कितने बाल बचे — वे सिर्फ छह लड़के थे, बचपन से एक दोपहर उधार ले रहे थे।

मुख्य बिंदु — बुजुर्गों के लिए सलाह

- 1. दोस्ती दवा हैः शोध बताते हैं — नियमित मिलना, खुलकर हंसना बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और अकेलेपन को कम करता है

- 2. हंसी सेहत हैः हंसी से दिल बेहतर, नींद अच्छी, इम्यूनिटी मजबूत

- 3. यादें जवान रखती हैंः पुरानी कहानियां दिमाग को सक्रिय रखती हैं, अल्जाइमर और भूलने की बीमारी से बचाव में मदद

- 4. बीमारियां भूल जाती हैंः दोस्तों के साथ समय में दवाइयों से ज्यादा सुकून मिलता है — क्योंकि दिल हल्का होता है।

विस्तृत विश्लेषण

1. सत्तर के बाद क्या चाहिए?

जन्मदिन नहीं, दोपहरें चाहिए। ऐसी दोपहरें जहाँ ओहदा, पैसा, कार, बीमारी मायने न रखे। जहाँ आप फिर से क्लास के लास्ट बेंच वाले लड़के बन जाएं। अकेलापन आज बुजुर्गों की सबसे बड़ी महामारी है — बच्चे बाहर, शरीर थका, दोस्त छूट गए। ऐसे में दोस्तों की टोली ही परिवार बन जाती है।

2. दोस्तों के साथ बीमारियां कैसे दूर होती हैं?

- मानसिक स्वास्थ्यः खुलकर बात करने से चिंता और अवसाद घटता है

- हृदय स्वास्थ्यः हंसी और खुशी से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नियंत्रित

- सामाजिक जुड़ावः मिलने-जुलने से अकेलेपन का जहर उतरता है

- याददाश्तः पुरानी बातें याद करने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है

- जीने की इच्छाः दोस्त कहते हैं — "तू अभी भी वही है₹ — यह वाक्य ही जीवन देता है

3. जीवनशैली में क्या करें?

- हर महीने कम से कम एक बार स्कूल-कॉलेज के दोस्तों से मिलें

- वॉट्सऐप ग्रुप नहीं, आमने-सामने मिलना तय करें — लास्ट बेंच वाली जगह ढूंढें

- चाय, कॉफी, पुरानी फोटो, स्कूल की कहानियां — यही दवा है

- नए दोस्त भी बनाएं — पार्क, मंदिर, योग क्लास में

- परिवार को भी बताएं — बुजुर्ग को दोस्तों से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें, रोकें नहीं

संपादकीय टिप्पणी

>झुर्रियां चेहरे पर आती हैं, पर दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती। सत्तर साल में आपको और दवाइयों की नहीं, और दोपहरों की जरूरत है — ऐसी दोपहरें जहाँ आप फिर से छह लड़के बन जाएं। क्योंकि अंत में, यादें ही साथ रहती हैं और दोस्ती ही बीमारियों को दूर करती है।



कानपुर में राजस्थान हाईकोर्ट रॉयल लॉयर्स क्रिकेट क्लब का शानदार प्रदर्शन, प्लेट ग्रुप में बना उपविजेता

--- राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के अधिवक्ताओं ने लहराया परचम, अब जयपुर में होगा टूर्नामेंट का अगला संस्करण



जयपुर। कानपुर में आयोजित 8वें ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान हाईकोर्ट रॉयल लॉयर्स क्रिकेट क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेट ग्रुप में उपविजेता का खिताब हासिल किया। कप्तान एडवोकेट अमित छंगाणी और उपकप्तान अमित पारीक के नेतृत्व में टीम ने अनुशासन, खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का गौरव बढ़ाया।

क्लब के सदस्य महेश दुबे, विलियम पाठक, पवन कुमार पाण्डेय और सुभाष सैनी ने बताया की इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा इंडियन एडवोकेट्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में 17 से 21 अक्टूबर 2026 तक आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने किया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हाई कोर्ट की कुल 12 टीमों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

राजस्थान हाईकोर्ट रॉयल लॉयर्स क्रिकेट क्लब ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन टीमवर्क और प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना का परिचय दिया। प्लेट ग्रुप में उपविजेता बनना टीम की निरंतर मेहनत, सामूहिक प्रयास और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है।

क्लब के लिए यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है। टूर्नामेंट के आठ संस्करणों में राजस्थान हाईकोर्ट रॉयल लॉयर्स क्रिकेट क्लब अब तक तीन बार उपविजेता और दो बार सेमीफाइनलिस्ट रह चुका है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर क्लब की निरंतर मजबूत उपस्थिति और क्रिकेट के प्रति अधिवक्ताओं के उत्साह को दर्शाती है।

इस सफलता के साथ राजस्थान के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। आयोजकों ने टूर्नामेंट का अगला संस्करण जयपुर में आयोजित करने की घोषणा की है। इससे जयपुर को देशभर के अधिवक्ताओं की क्रिकेट प्रतिभा की मेजबानी करने का अवसर मिलेगा और राजस्थान की खेल एवं अधिवक्ता जगत में पहचान को और मजबूती मिलेगी।

इस उपलब्धि पर रवि सूर्य ग्रुप के चेयरमैन एवं क्रेडाई अध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह तथा कोरल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गिर्राज डागा ने टीम को शानदार प्रदर्शन और उपविजेता बनने पर शुभकामनाएं दीं। साथ ही, आगामी संस्करण की मेजबानी जयपुर को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया।

राउरकेला महानगर निगम की टैक्सी निविदा पर सवाल, अवधि समाप्त होने के बाद भी नई निविदा का इंतजार

प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में देरी से उठे पारदर्शिता के सवाल, जिम्मेदारी संभाल रहे आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका भी चर्चा में

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार राउरकेला



राउरकेला महानगर निगम में नियुक्त कर्मचारियों हेतु निमित्त टैक्सी सेवा से संबंधित निविदा प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि मौजूदा ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद नई निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी नहीं की गई है। इससे उन संभावित निविदादाताओं में असंतोष है, जो इस प्रक्रिया में भाग लेकर प्रतिस्पर्धी आधार पर काम हासिल करना चाहते हैं। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी नई निविदा की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से निगम की कार्यप्रणाली और निविदा प्रबंधन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

निविदा प्रक्रिया में देरी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे प्रतिस्पर्धा के समान अवसर प्रभावित होने की आशंका पैदा होती है। यदि किसी सेवा का अनुबंध समाप्त हो चुका है, तो उसके आगे संचालन, नई निविदा जारी करने और अंतरिम व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि आखिर नई निविदा की प्रक्रिया किस स्तर पर अटकी हुई है और इसके लिए जवाबदेह कौन है।

इस मामले में कुछ संभावित भागीदारों ने कथित साठगांठ की आशंका भी जताई है। हालांकि, अभी तक ऐसी किसी मिलीभगत के समर्थन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित दस्तावेज या आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं। इसलिए इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और निगम की ओर से स्पष्ट जवाब आवश्यक है।

मामले का एक अन्य पहलू टैक्सी सेवा से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे एक आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति और उसके वर्तमान कार्यभार को लेकर उठ रहे सवाल हैं। आरोप है कि आउटसोर्स निविदा के तहत अन्य संबंधित कर्मचारियों को हटाए जाने के बावजूद उक्त कर्मचारी अब भी कार्यरत है। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल और वर्तमान जिम्मेदारी के आधार पर निगम को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

संबंधित कर्मचारी का पक्षः इस संबंध में जब संबंधित कर्मचारी से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, "मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करता हूं।" फिलहाल उनका विस्तृत पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है।

अब सवाल राउरकेला महानगर निगम के प्रशासनिक नेतृत्व से है कि नई निविदा जारी करने में देरी क्यों हो रही है, वर्तमान व्यवस्था किस आधार पर चल रही है और जिम्मेदार कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित नियमों का पालन हुआ है या नहीं। निगम को निविदा की समयसीमा, अनुबंध की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना सार्वजनिक करनी चाहिए। सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता केवल नियमों की औपचारिकता नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति विश्वास की बुनियाद है।

सिंचाई नहर की बदहाली से हादसे का खतरा, दो मासूमों की मौत के बाद भी नहीं चेता विभाग!

वेदव्यास से गोपीपाली तक नहर पर अतिक्रमण और गंदगी के आरोप, सफाई के दावे पर उठे सवाल; जांच के दायरे में सरकारी खर्च

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला



राउरकेला के अन्तर्गत वेदव्यास के अधीन ब्राह्मणीतरंग समीप कादोबाहल क्षेत्र से गोपाली तक जाने वाली सिंचाई नहर की बदहाल स्थिति ने एक बार फिर सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नहर में कथित अतिक्रमण, लंबे समय से सफाई नहीं होने और जलप्रवाह क्षेत्र में जमा गंदगी को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि वर्ष 2022-23 में इसी नहर में फंसने से दो नवजात शिशुओं की मृत्यु होने की जानकारी सामने आई थी। ऐसे दुखद घटनाक्रम के बाद भी यदि नहर की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो यह संबंधित विभाग की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

नहर का उद्देश्य खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, लेकिन रखरखाव में लापरवाही और अतिक्रमण के आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे सिंचाई व्यवस्था के साथ जनसुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। नहर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह केवल सरकारी संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं से जुड़ा गंभीर विषय है।

इस संबंध में पितामहल सिंचाई विभाग के एसडीओ से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए तहसील कार्यालय को आवेदन दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले महीने नहर की सफाई कराई गई थी। हालांकि, उपलब्ध तस्वीरों में दिखाई देने वाली स्थिति इस दावे की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पैदा करती है। तस्वीरें अपने आप में फर्जी बिलिंग का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन यदि स्थल की वास्तविक स्थिति और सरकारी अभिलेखों में दर्ज सफाई कार्य में अंतर मिलता है, तो भुगतान तथा कार्य निष्पादन की जांच जरूरी होगी।

अब सबसे बड़ा सवाल सरकारी धन के इस्तेमाल का है। सफाई किस एजेंसी ने की, कार्यादेश कब जारी हुआ, कितनी राशि का भुगतान किया गया और काम की गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी ने की— इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। यदि कागजों पर सफाई और जमीन पर बदहाली के बीच अंतर प्रमाणित होता है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रशासन को नहर का स्थल निरीक्षण कर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा सफाई कार्य के अभिलेखों और भुगतान का सत्यापन कराना चाहिए। दो मासूमों की मौत की दर्दनाक याद के बीच अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं।

नहर की सफाई, अतिक्रमण हटाने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई ही विभाग की जवाबदेही की वास्तविक कसौटी होगी।

न्यू हॉराइज़न स्कूल में मनाया गया 47वां वार्षिक महोत्सव "From Dream to Reality A Journey of Science"

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक





न्यू हॉराइज़न स्कूल, निज़ामुद्दीन ने विद्यालय परिसर में अपना '47 वां वार्षिक महोत्सव' बड़ी धूम धाम से मनाया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रो. (डॉ.) एस. फ़ारूक़ (अध्यक्ष - हिमालय वेलनेस कंपनी, चेयरमैन तसमिया ऑल इंडिया एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी) एवं गेस्ट ऑफ़ ऑनर आदरणीय श्री पंकज राग (IAS, जोइंट सेक्रेटरी (सेवा निवृत्त) मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर, भारत सरकार) की गरिमामयी उपस्थिति रही, साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए थानाध्यक्ष हज़रत निज़ामुद्दीन व अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य व अध्यापक रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि आदरणीय प्रो.(डॉ.) एस. फ़ारूक़, श्रीमान पंकज राग (IAS) ने ज्योति प्रज्ज्वलन के साथ किया। उपरांत स्कूल प्रबंधन समिति जनाब शबी अहमद (अध्यक्ष - वर्ल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन), जनाब कमाल फ़ारूक़ी (चेयरमैन), जनाब प्रो. मो. नक़ी (मैनेजर) द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रो. एस. फ़ारूक़, श्री पंकज राग, जनाब शबी अहमद व कमाल फ़ारूक़ी का वक्तव्य हुआ। उपरांत स्कूल की प्रिंसिपल मिस. सुमेरा ख़ान ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत की, जिसमे सत्र 2025-26 की सम्पूर्ण गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, सरकारी, ग़ैर सरकारी प्रतियोगताओ में उपलब्धियों को शामिल किया गया। इस सुअवसर पर न्यू हॉराइज़न स्कूल ने ₹कॉफ़ी टेबल बुक₹ का लोकार्पण भी किया, जिसमें स्कूल के स्वर्णिम इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति और भविष्य के लक्ष्य की रूपरेखा है। इस वर्ष वार्षिक महोत्सव की थीम ₹From Dreams to Reality A Journey of Science₹ रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से न्यू हॉराइज़न स्कूल ने आदिकाल से लेकर अबतक के ज्ञान-विज्ञान, बुद्धि, जिज्ञासा, परंपरा, संगम, उपलब्धियों की यात्रा का मिलाजुला संगम दर्शाया, जिसमें गीत, संगीत, नाट्य, नृत्य, इतिहास- वर्तमान व भविष्य आदि का मिलाजुला संगम रहा। अंत में प्रधानाचार्या सुमेरा ख़ान द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया। मुख्य अतिथि, अतिथि, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावकों व विद्यार्थियों द्वारा इस रंगारंग कार्यक्रम को बहुत सराहा गया और कहा गया कि न्यू हॉराइज़न स्कूल अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।

जवाबदेह पुलिस व्यवस्था से ही बनेगा सुरक्षित उत्तर प्रदेश

सौरभ वार्ष्णेय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर यह संदेश दिया कि नए उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इसी स्वतंत्रता के कारण प्रदेश की पहचान उपद्रव से उत्सव की ओर बदली है। उनका यह वक्तव्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और पुलिस की भूमिका को रेखांकित करता है। निस्संदेह, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांति, सुरक्षा और कानून का शासन विकास की बुनियादी शर्तें हैं। लेकिन कानून के राज की वास्तविक सफलता केवल सख्त कार्रवाई के दावों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा के विश्वास, न्याय की उपलब्धता और प्रशासन की निष्पक्षता से तय होती है।

पुलिस स्मृति दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन वीर पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने देश और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलिस का दायित्व केवल अपराधियों को पकड़ना या कानून का पालन कराना नहीं है, बल्कि संकट के समय नागरिकों की सहायता करना, कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में विश्वास का वातावरण तैयार करना भी है। कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और अनुशासन पुलिस सेवा की पहचान हैं। ऐसे में शहीद पुलिसकर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी, जब पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, उनके कार्य करने की परिस्थितियों, आधुनिक संसाधनों और पेशेवर प्रशिक्षण को लगातार बेहतर बनाया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले की कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में माफिया और अराजक तत्वों का प्रभाव था। मथुरा के जवाहर बाग जैसी घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि कानून-व्यवस्था की चुनौतियां कितनी गंभीर हो सकती हैं और उनसे निपटने में पुलिसकर्मियों को किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान सरकार का दावा है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव को बाधा नहीं बनने दिया जा रहा। यदि इस नीति को निष्पक्षता और निरंतरता के साथ लागू किया जाता है, तो इससे कानून के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हो सकता है।

हालांकि, किसी भी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह कानून व्यवस्था में सुधार का आकलन केवल अपनी उपलब्धियों के आधार पर न करे, बल्कि स्वतंत्र आंकड़ों, अपराध के बदलते स्वरूप और नागरिकों के अनुभवों को भी महत्व दे। अपराध पर नियंत्रण का अर्थ केवल गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की संख्या बढ़ाना नहीं है। वास्तविक उपलब्धि तब मानी जाएगी, जब महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, व्यापारियों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित वातावरण मिले। शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों को परेशान न होना पड़े, पीड़ितों को समय पर सहायता मिले और अपराध की जांच निष्पक्ष ढंग से पूरी हो। पुलिस की सक्रियता के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया की गति और अभियोजन की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए 2.26 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण क्षमता में दस गुना वृद्धि, सात बड़े शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने, प्रत्येक जिले में साइबर थाने स्थापित करने और सभी थानों में महिला सहायता कक्षों की व्यवस्था जैसे कदमों का उल्लेख किया। इन पहलों का उद्देश्य पुलिस को बदलती सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना है। बढ़ती आबादी और तेजी से शहरीकरण के बीच उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पुलिस बल की संख्या, उसकी दक्षता और संसाधनों का विस्तार आवश्यक है। नई भर्तियों से पुलिस पर काम का दबाव कम करने, गश्त बढ़ाने और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

लेकिन भर्ती के साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पुलिसकर्मियों को कानून, मानवाधिकार, साइबर अपराध, फॉरेंसिक जांच, डिजिटल साक्ष्य और सामुदायिक पुलिसिंग का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। केवल आधुनिक हथियार और तकनीकी उपकरण उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। पुलिस की कार्यशैली में संवेदनशीलता, धैर्य और पेशेवर व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। किसी पीड़ित की शिकायत सुनने से लेकर अपराध की जांच पूरी करने तक हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। पुलिस की प्रतिष्ठा उसके अधिकारों से ही नहीं, बल्कि उन अधिकारों के जिम्मेदार इस्तेमाल से भी बनती है। आज साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों ने पुलिस के सामने नई जिम्मेदारियां खड़ी कर दी हैं। प्रत्येक जिले में साइबर थानों की स्थापना एक उपयोगी कदम है, लेकिन इन थानों में प्रशिक्षित कर्मचारियों, आधुनिक तकनीक और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था भी जरूरी है। आम नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने में सरलता मिलनी चाहिए। इसी तरह महिला सहायता कक्षों की स्थापना तभी प्रभावी होगी, जब महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए, उनकी गोपनीयता सुरक्षित रखी जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।

सरकार ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत 88,973 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त किए जाने का उल्लेख किया है। ये आंकड़े संगठित अपराध और अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध सरकार की कार्रवाई का संकेत देते हैं। अपराध से अर्जित संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई संगठित अपराध के आर्थिक आधार को कमजोर करने का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। फिर भी ऐसी कार्रवाई में कानून की निर्धारित प्रक्रिया, पर्याप्त साक्ष्य और निष्पक्ष जांच का पालन अनिवार्य है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई का आधार उसका अपराध होना चाहिए, न कि उसकी राजनीतिक पहचान, सामाजिक स्थिति या किसी अन्य प्रकार का पूर्वाग्रह। कानून की शक्ति तभी विश्वसनीय बनती है, जब उसका प्रयोग सभी के लिए समान हो।

यह भी समझना होगा कि पुलिस को स्वतंत्रता देने का अर्थ उसे जवाबदेही से मुक्त करना नहीं है।

रचनात्मक संवाद और संघर्ष ही समय की मांग - संदीप दीक्षित

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा



भुवनेश्वर: देश के वर्तमान निर्णायक दौर में रचनात्मक संवाद और संघर्ष ही एकमात्र विकल्प हैं। इनके माध्यम से राजनीतिक दलों से बाहर रहने वाले देश के असंख्य लोगों को एकजुट करना संभव है और संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा भी की जा सकती है। यह बात पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कही। गुरुवार सुबह भुवनेश्वर स्थित लोहिया अकादमी में देवी प्रसाद पृष्टि की अध्यक्षता में आयोजित *रचनात्मक चिंतन बैठक* में संदीप दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज भारत बेरोजगारी, गरीबी और खराब शिक्षा व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। भाजपा और प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए खतरनाक साजिश रच रहे हैं, जो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। दीक्षित ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिखाया गया रास्ता ही रचनात्मकता का मार्ग है। राहुल गांधी द्वारा विभाजन, वैमनस्य और नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की राजनीति करना स्वागतयोग्य है। इसकी पुष्टि भारत जोड़ो यात्रा से होती है। उन्होंने ओडिशा के लोगों से रचनात्मक संवाद के माध्यम से भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार होने का आह्वान किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि धनबल की राजनीति और वोट चोरी को पराजित करने के लिए जनता का सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा में रचनात्मक क्रांति की नींव पड़ी है। आने वाले दिनों में पूरे राज्य में जनसंपर्क, समन्वय और संवाद के माध्यम से व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने लोगों से निःस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्य करने की अपील की। वहीं, प्रसाद हरिचंदन ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ जनमत को जागृत कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक और देशभक्तिपूर्ण कार्य होगा। बैठक में शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और पूर्व प्रशासकों सहित कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। इनमें नलिनी रंजन महांति, संदीप पटनायक, श्रीचरण बेहरा, पल्लवी मिश्रा, सरिता बड़पंडा, अनिल धीर, कपिलेश्वर मिश्रा, सरोज सतपथी, डॉ. पंचानन कानूनगो, केदार मिश्रा, विधायक डॉ. राजन एक्का, देवप्रसाद राय महापात्र, सजलेंदु मालाकार, अरविंद बेहरा, कस्तूरी खटई, तुषार राय, प्रताप रथ, पूर्णेंदु मिश्रा, सुधांशु देव, सुदर्शन दास, कर्मा लाकड़ा और रजनी महांति सहित अन्य लोग शामिल थे।

प0सिंहभूम में15 लापरवाह रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति की तरफ बढ़ा प्रशासन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड



रांची, पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीण विकास कार्यों में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने वाले 15 ग्राम रोजगार सेवकों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है।

कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं करने और नियुक्ति के बाद योगदान नहीं देने के मामलों में इनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इनके स्थान पर दिसंबर 2025 में तैयार प्रतीक्षा सूची से 15 नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जिला प्रशासन ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम रोजगार सेवकों के कार्यों और प्रदर्शन की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।

प्रशासन के अनुसार, दिसंबर 2025 में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इनमें से छह ने नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद जिले में योगदान नहीं दिया। इसलिए उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

वहीं, विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित सात ग्राम रोजगार सेवक लगातार अपने निर्धारित कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। इनमें जगन्नाथपुर के एक, हाटगम्हरिया के दो, नोवामुंडी के एक, कुमारडुंगी के एक और टोंटो के दो ग्राम रोजगार सेवक शामिल हैं।

इसके अलावा सदर चाईबासा प्रखंड में पदस्थापित दो ग्राम रोजगार सेवकों के कार्यों की समीक्षा में निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर उन्हें भी हटाने का निर्णय लिया गया।

रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से 15 नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, लगातार अनुपस्थिति और जिम्मेदारियों के निर्वहन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

झारखंड के युवा क्रिकेटर शिखर का चयन भारतीय टीम में न्यूजीलैंड दौरे के लिए

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड के युवा बल्लेबाज शिखर मोहन ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के दम पर नई पहचान बनाई है. रांची के डोरंडा में पले-बढ़े 21 वर्षीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का चयन न्यूज़ीलैंड दौरे के लिए भारत-ए की टेस्ट टीम में हुआ है. इस चयन को उनके क्रिकेट करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. घरेलू मुकाबलों में लगातार रन बनाने वाले शिखर से अब आगामी अवसरों पर भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. हालांकि, भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें आगे भी अपनी क्षमता साबित करनी होगी.

शिखर ने कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. छह वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लेना शुरू किया. वह जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के छात्र रहे हैं. इसी स्कूल से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी पढ़ाई की थी. झारखंड की घरेलू टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शिखर ने अपनी बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है.

शिखर के प्रदर्शन की चर्चा उनके रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र से भी जुड़ी है. 2025-26 सत्र में झारखंड की ओर से खेलते हुए उन्होंने 55.71 की औसत से 613 रन बनाए. इस दौरान नागालैंड के खिलाफ दोहरा शतक और बड़ौदा के विरुद्ध शतकीय पारी खेली. इन प्रदर्शनों ने उन्हें झारखंड के उभरते बल्लेबाजों में शामिल किया.

इसके अलावा, दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए उन्होंने 85 रन की पारी खेली. ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में भी उन्हें जगह मिली, जहां उन्होंने 60 रन बनाए. लगातार अलग-अलग घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने और रन बनाने से उन्हें बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है.

झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने शिखर मोहन के चयन को राज्य के लिए गौरव की बात बताया. उन्होंने कहा कि झारखंड से लगातार बेहतर क्रिकेटर निकल रहे हैं. शिखर प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है. उम्मीद है कि वह आने वाले समय में भारतीय टीम में भी जगह बनाएंगे. उन्होंने शिखर को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं.

चोटिल ऋषभ पंत की जगह शिखर मोहन को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने इसकी पुष्टि की है. शिखर मोहन को दूसरे और तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच के लिए टीम में चुना गया है. दोनों मुकाबले चार दिवसीय होंगे. पंत के चोटिल होने के बाद शिखर को टीम में मौका मिला है.

भारत-ए की टेस्ट टीम में चयन शिखर के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का एक और अवसर है. इस स्तर पर प्रदर्शन से उन्हें अनुभव हासिल करने और आगे के लिए दावेदारी मजबूत करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सीनियर भारतीय टीम में चयन प्रदर्शन, टीम की जरूरत और चयनकर्ताओं के फैसले पर निर्भर करेगा. फिलहाल शिखर के सामने न्यूज़ीलैंड दौरे पर मिले अवसर का लाभ उठाने और अपनी निरंतरता बनाए रखने की चुनौती है. रांची के इस युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन पर अब झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों की भी नज़र रहेगी.

रांची ,झारखंड के युवा बल्लेबाज शिखर मोहन ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के दम पर नई पहचान बनाई है. रांची के डोरंडा में पले-बढ़े 21 वर्षीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का चयन न्यूज़ीलैंड दौरे के लिए भारत-ए की टेस्ट टीम में हुआ है. इस चयन को उनके क्रिकेट करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. घरेलू मुकाबलों में लगातार रन बनाने वाले शिखर से अब आगामी अवसरों पर भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. हालांकि, भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें आगे भी अपनी क्षमता साबित करनी होगी.

शिखर ने कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. छह वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लेना शुरू किया. वह जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के छात्र रहे हैं. इसी स्कूल से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी पढ़ाई की थी. झारखंड की घरेलू टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शिखर ने अपनी बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है.

शिखर के प्रदर्शन की चर्चा उनके रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र से भी जुड़ी है. 2025-26 सत्र में झारखंड की ओर से खेलते हुए उन्होंने 55.71 की औसत से 613 रन बनाए. इस दौरान नागालैंड के खिलाफ दोहरा शतक और बड़ौदा के विरुद्ध शतकीय पारी खेली. इन प्रदर्शनों ने उन्हें झारखंड के उभरते बल्लेबाजों में शामिल किया.

इसके अलावा, दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए उन्होंने 85 रन की पारी खेली. ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में भी उन्हें जगह मिली, जहां उन्होंने 60 रन बनाए. लगातार अलग-अलग घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने और रन बनाने से उन्हें बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है.

जनता से संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्व तट रेलवे ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किया 'जन संवाद'

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा



भुवनेश्वर :पूर्व तट रेलवे की ओर से आज विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 'जन संवाद' अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेलवे और आम जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना, यात्रियों को जागरूक करना तथा रेल सेवाओं में सुधार के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम के तहत पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने रेल सेवाओं और यात्री सुविधाओं के संबंध में यात्रियों की राय एवं सुझाव प्राप्त किए। इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा भी की। महाप्रबंधक ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा रेलवे स्टेशन परिसर को स्वच्छ और यात्री-अनुकूल बनाए रखने पर जोर दिया। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान का भी नेतृत्व किया। उन्होंने यात्रियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने में साफ-सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल में रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया तथा रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ, सुंदर और यात्री-अनुकूल बनाए रखने के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।

'जन संवाद' अभियान रेलवे अधिकारियों, यात्रियों और आम जनता के बीच सीधे संवाद के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से यात्रियों की आवश्यकताओं को समझने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा रेल सेवाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने में मदद मिल रही है। अभियान के दौरान रेलवे अधिकारी और कर्मचारी यात्री सुरक्षा, स्वच्छता, जिम्मेदार यात्रा तथा रेलवे परिसर के उचित उपयोग के संबंध में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

यह अभियान यात्रियों को स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं, यात्री-संबंधी सेवाओं और यात्रा के समग्र अनुभव के बारे में अपनी राय एवं सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस तरह के सीधे संवाद से रेलवे प्रशासन को आम जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने तथा सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल रही है।

जनता से संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्व तट रेलवे ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किया 'जन संवाद' अभियान

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा



भुवनेश्वर :पूर्व तट रेलवे की ओर से आज विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 'जन संवाद' अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेलवे और आम जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना, यात्रियों को जागरूक करना तथा रेल सेवाओं में सुधार के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम के तहत पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने रेल सेवाओं और यात्री सुविधाओं के संबंध में यात्रियों की राय एवं सुझाव प्राप्त किए। इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा भी की। महाप्रबंधक ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा रेलवे स्टेशन परिसर को स्वच्छ और यात्री-अनुकूल बनाए रखने पर जोर दिया। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान का भी नेतृत्व किया। उन्होंने यात्रियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने में साफ-सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल में रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया तथा रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ, सुंदर और यात्री-अनुकूल बनाए रखने के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।

'जन संवाद' अभियान रेलवे अधिकारियों, यात्रियों और आम जनता के बीच सीधे संवाद के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से यात्रियों की आवश्यकताओं को समझने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा रेल सेवाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने में मदद मिल रही है। अभियान के दौरान रेलवे अधिकारी और कर्मचारी यात्री सुरक्षा, स्वच्छता, जिम्मेदार यात्रा तथा रेलवे परिसर के उचित उपयोग के संबंध में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

यह अभियान यात्रियों को स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं, यात्री-संबंधी सेवाओं और यात्रा के समग्र अनुभव के बारे में अपनी राय एवं सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस तरह के सीधे संवाद से रेलवे प्रशासन को आम जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने तथा सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023